लखनऊ

मंगलवार, 12 मई, 2026

वर्ष : 11 | अंक: 257

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"जिस दिन पढ़ाई बोझ नहीं, सपना लगने लगे उस दिन सफलता आपके कदम चूमने लगेगी।"

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 26° Low

संक्षेप

बलिदानी अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों जैसी पेंशन नहीं, केंद्र ने अदालत को बताया कारण

मुंबई, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन से जुड़े लाभ के मामले में अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के बीच कोई बराबरी नहीं है। सरकार का कहना है कि दोनों की सेवा शर्तें और कार्यकाल बिल्कुल अलग हैं। इसलिए युद्ध या किसी अभियान में जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को नियमित सैनिकों के परिवारों की तरह लंबी अवधि वाली पेंशन नहीं दी जा सकती है। यह जवाब सरकार ने एक शहीद अग्निवीर की मां की याचिका पर दिया है और साफ किया है कि दोनों श्रेणियों में कोई समानता नहीं है। यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से जुड़ा है। यह याचिका पिछले साल जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से हुई गोलाबारी में जान गंवाने वाले अग्निवीर मुरली नाइक की मां ज्योतिबाई नाइक ने दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि उनके बेटे को भी नियमित सैनिकों की तरह ही सभी लाभ और परिवार को पूरी पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। याचिका में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया था। इसी याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते अपना हलफनामा दायर कर सारी स्थिति साफ की है और याचिका खारिज करने की मांग की है। सरकार ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट को बताया है कि अग्निवीर और नियमित सैनिक एक समान स्थिति में नहीं आते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती केवल चार साल के तय समय के लिए की जाती है। वहीं, दूसरी तरफ सशस्त्र बलों में नियमित सैनिकों की सेवा लंबी अवधि की होती है।

टीएमसी का दावा- 31 सीटों पर जीत का अंतर SIR की वोट कटौती से कम; अदालत ने दिए ये निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान काटे गए वोटों के मुकाबले विधानसभा सीटों में जीत के कम अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों को इस संबंध में नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी है। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सोमवार को दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची शामिल थे। यह मामला तब सामने आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद कल्याण बनर्जी ने अदालत में यह दलील दी कि राज्य की 31 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर, मतदाता सूची से हटाई गई वोटों की संख्या से कम रहा। इस मामले में चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसे दावों के लिए चुनाव याचिका ही एकमात्र उचित माध्यम है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वह एसआईआर से संबंधित मुद्दों और वोट जोड़ने या हटाने के खिलाफ होने वाली अपीलों के लिए जवाबदेह हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इन दलीलों पर ध्यान देते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए नई याचिकाएं दायर करने का अवसर दिया।

'कोई ताकत भारत को नहीं झुका सकती', पीएम मोदी का बयान; तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बरसे

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश में कुछ ताकतें राष्ट्रीय आत्मसम्मान से ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध के दौरान भी इसी तरह की मानसिकता देखी जाने का जिक्र किया।

गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अथक प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध का सामना करना पड़ा था।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को झुकने या दबाव के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव को समर्पित पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने के लिए यहां आए थे।

ऐसी मानसिकता के प्रति सतर्क रहना चाहिए

उन्होंने आगे कहा, 'फिर भी, हमारे देश में राष्ट्रीय आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी राजनीति खेली गई, और सोमनाथ मंदिर इसका एक प्रमुख उदाहरण है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली ताकतें अभी भी देश में सक्रिय हैं। हमने राम मंदिर के निर्माण के दौरान भी इसी तरह की घटना देखी और जिस तरह से इसका विरोध किया गया था। हमें इस तरह की मानसिकता के प्रति सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की संकीर्ण राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'हमें विकास और विरासत दोनों को साथ-साथ अपनाकर आगे बढ़ना होगा। वास्तव में, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा हमारी प्रगति में बाधा बनी हुई है।' इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के तहत सोमनाथ मंदिर में महा पूजा और अन्य अनुष्ठान किए।

विरासत को पुनर्स्थापित किया

उन्होंने कहा कि 11 मई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने इसी तारीख (1998 में) परमाणु परीक्षण किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'विश्व भर में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जहां विदेशी आक्रमणकारियों ने राष्ट्र की पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट कर दिया। जब भी लोगों को अवसर मिला उन्होंने अपनी विरासत को पुनर्स्थापित किया और अपनी गरिमा को बनाए रखा।'

पीएम मोदी की सलाह पर केजरीवाल का बड़ा हमला, पूछा- क्या देश में आर्थिक आपातकाल है?

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों को एक साल तक सोने पर खर्च न करने और खाना पकाने के तेल की खपत कम करने के सुझाव पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी को जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को खाने-पीने, यात्रा और पर्यटन पर खर्च कम करने और यहां तक कि सोने और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीद पर भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक आपातकाल का संकेत है? क्या देश गंभीर आर्थिक संकट में डूबा हुआ है?

बंगाल में घुसपैठियों पर गिरेगी गाज! सुवेंदु अधिकारी का बीएसएफ को ग्रीन सिग्नल, 45 दिन में लगेगी बाड़

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि सौंपने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। यह निर्णय भाजपा के उस प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करता है जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से निपटने पर केंद्रित था। विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के कुछ दिनों बाद, नबन्ना (राज्य सचिवालय) में पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अधिकारी ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि पर बीएसएफ का पूर्ण नियंत्रण होगा। अधिकारी ने बताया कि आज हुई हमारी पहली कैबिनेट बैठक में हमने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का फैसला लिया है। यह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और अगले 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या का समाधान अल्पकाल में हो जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम अधिकारी की पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ यह पहली आमने-सामने वाली मीटिंग होगी। जिसमें पुलिस अधिकारियों को पुराने तरीके छोड़ते हुए लोगों को सुरक्षत माहौल देते हुए नई पुलिसिंग में आना होगा। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल की पुलिस में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा।

मुख्यमंत्री विजय ने की एमके स्टालिन से मुलाकात, सियासी गलियारों में चर्चा तेज

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को अपने पूर्ववर्ती एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम. के. स्टालिन से यहां अलवरपेट स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। विजय के नेतृत्व वाली सरकार को 13 मई तक सदन में विश्वास मत हासिल करना है, उससे कुछ दिन पहले दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विजय ने पहली बार स्टालिन से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह एक "शिष्टाचार भेंट" थी। स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय का गर्मजोशी से स्वागत किया। विजय द्वारा तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण बोझ होने के लिए द्रमुक की पूर्ववर्ती सरकार की कड़ी आलोचना करने के एक दिन बाद यह बैठक हुई है।

'सबका साथ, सबका विकास' ही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत, मुख्यमंत्री बनने के बाद बोले सुवेंदु

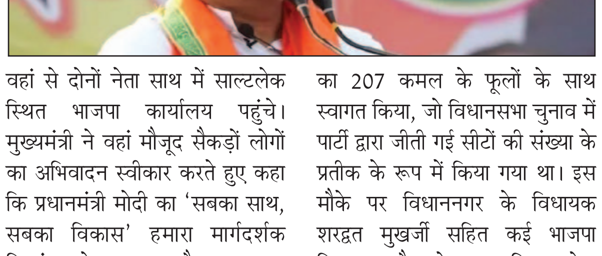

कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का दृष्टिकोण राज्य में नई भाजपा सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन राज्य सचिवालय नवान्न में अपनी पहली कैबिनेट की बैठक से पहले कोलकाता के साल्टलेक स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के साथ संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार साल्टलेक में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उससे ठीक पहले अधिकारी ने साल्टलेक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भट्टाचार्य के निवास स्थान पर भी गए। वहां से दोनों नेता साथ में साल्टलेक स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। इस दौरान भाजपा कार्यालय को फूलों से सजाया गया था। वहां जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र और 'भारत माता' की तस्वीर लगाई गई थी। पार्टी कार्यालय में 'जय श्रीराम' के नारों के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधिकारी का 207 कमल के फूलों के साथ स्वागत किया, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के प्रतीक के रूप में किया गया था। इस मौके पर विधाननगर के विधायक शरद्वत मुखर्जी सहित कई भाजपा विधायक और प्रदेश महासचिव लाकेट चटर्जी सहित सौमित्र खां मौजूद रहे। इससे पहले सुबह न्यूटाउन इलाके में स्थित अपने आवास से निकलते समय अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। हमें लोगों के लिए काफी काम करना है।

'आजादी के बाद मजदूरों के अधिकारों को सबसे बड़ा झटका', चार नए लेबर कोड लागू करने पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में लागू हुए चार नए लेबर कोड पर आपत्ति जताते हुए इसे मजदूरों के हितों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी सलाह के चार नए लेबर कोड लागू कर दिए।

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार विधानसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार करती रही। इसके बाद 8 और 9 मई 2026 को गजट (राजपत्र) अधिसूचना जारी करके चार मजदूर-विरोधी श्रम संहिताओं को लागू कर दिया। भारत के करोड़ों मजदूरों के लिए ये संहिताएं 'हायर एंड फायर' की नीति ला रही हैं। यानी नौकरी पर जब चाहे रख लो और जब चाहे निकाल दो। साथ ही ठेका (कॉन्ट्रैक्ट) पर रोजगार बढ़ेगा और ट्रेड यूनियन बनाने की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार ने इन मजदूर-विरोधी संहिताओं का मसौदा तैयार किया और उन्हें बिना किसी परामर्श के लागू कर दिया। इसने 2015 के बाद से 'भारतीय श्रम सम्मेलन' भी नहीं बुलाया है। आजादी के बाद से मजदूरों के अधिकारों के लिए सबसे बड़ा झटका है।

न्यूनतम वेतन होगा कम: मल्लिकार्जुन खरगे

वेतन संहिता 2019 का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि यह पूरी वेतन संरचना 'मजदूर-केंद्रित' नहीं, बल्कि 'कॉर्पोरेट-केंद्रित' है। मोदी सरकार ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए विशिष्ट मानदंडों को हटा दिया है। इसके बजाय, मानदंड केंद्र सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश के माध्यम से अलग से निर्धारित किए जाएंगे। न्यूनतम वेतन अब दिशानिर्देशों और मानदंडों के एक तय सेट के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाएगा बल्कि केंद्र सरकार की मनमानी सनकों के अनुसार तय होगा। इसका परिणाम यह होगा कि न्यूनतम वेतन कम हो जाएगा। नए नियमों के तहत, मूल वेतन कुल पारिश्रमिक का 50 फीसदी या उससे अधिक होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए 'हाथ में आने वाले वेतन' में भारी कमी देखने को मिलेगी। 'वेतन' की एक जटिल और एकल परिभाषा ने वेतन संरचना को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया है, जिससे भत्ते कम हो गए हैं और भारी भ्रम पैदा हो गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर अतिरिक्त लागतों और डिजिटल अनुपालन का नया बोझ उनके अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन गया है। न्यूनतम वेतन सुरक्षा में कृषि मजदूरों और घरेलू सहायकों को शामिल नहीं किया गया है। खरगे ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि इस संहिता में कार्यस्थल पर सुरक्षा को नियोक्ता का अनिवार्य कर्तव्य मानने के बजाय, उसे सिर्फ व्यवसाय की एक अतिरिक्त लागत (खर्च) बना दिया गया है। यह संहिता 'अपराध-मुक्तिकरण' का ढांचा लाती है। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर चाहे उससे गंभीर चोट या दुर्घटना ही क्यों न हो अब आपराधिक मुकदमा चलाने के बजाय सिर्फ जुर्माना भरने की व्यवस्था है। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए एस्कॉर्ट, ट्रांसपोर्ट और सीसीटीवी कवरेज जैसे सुरक्षा उपायों के लिए कोई ठोस, अनिवार्य मॉडल नहीं है।

सोना मत खरीदो-तेल कम इस्तेमाल करो पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी ने कहा- ये नाकामी के सबूत

मध्य पूर्व में लगातार खराब होते हालात और खाड़ी संकट के बीच पीएम मोदी की आम जनता से तेल, गैस, सोने समेत कई चीजों पर संयम बरतने की अपील पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाए, कहां न जाए। ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज सोमवार को सोशल मीडिया X पर पीएम मोदी की अपील पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, "PM मोदी ने कल जनता से त्याग मांगे, कहा- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उनके उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं।" 1, 2026 राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 12 साल के शासन को लेकर कहा, "पिछले 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया है कि जनता को बताना पड़ रहा है- क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाएं और कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों पर कार्ति चिदंबरम का हमला

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए की गई सात अपीलों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। उक्त टिप्पणियों पर संसद का सत्र बुलाने का आग्रह करते हुए कार्ति चिदंबरम ने कहा कि ऐसी अपीलें नाटकीय हैं और संकेत देती हैं कि कुछ सामान्य नहीं है। कार्ति चिदंबरम ने एएनआई को बताया कि प्रधानमंत्री की यह अपील या निर्देश काफी नाटकीय है, जिसमें वे देश के नागरिकों से घर से काम करने, सोना न खरीदने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और निजी परिवहन से बचने का आग्रह कर रहे हैं। ये सभी अपीलें, निर्देश न सही, बहुत नाटकीय हैं। अगर प्रधानमंत्री ऐसी अपील कर रहे हैं, तो भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि सरकार को देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें संसद का सत्र बुलाकर हमें स्थिति से अवगत कराना चाहिए क्योंकि यह सामान्य स्थिति नहीं है... क्या सरकार देश से कुछ कड़वी सच्चाई छिपा रही है? हम वास्तव में यही जानना चाहते हैं। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करने के एक दिन बाद आईं, जहां उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती लागतों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने और जिम्मेदार उपभोग की आदतें अपनाने का आग्रह किया था।

घर चलाने वाली महिलाओं को रोजगार में 4 .4% अधिक मौके, परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है श्रम बाजार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत का महिला श्रम बाजार एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। शिक्षा, घर चलाने के मामलों में बढ़ती भूमिका और सामाजिक गतिशीलता की वजह से नियमित वेतन वाले रोजगार में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। एसबीआई रिसर्च की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जो महिलाएं अपने परिवार की मुखिया होती हैं, उनके नियमित वेतन वाले रोजगार में होने की संभावना अन्य महिलाओं के मुकाबले 4.4 फीसदी अधिक होती हैं, जबकि अनौपचारिक मजदूरी में 4.2% कम। महिलाओं की रोजगार स्थिति पर एसबीआई रिसर्च का यह विश्लेषण पहली बार भारत के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के यूनिट-लेवल डाटा के आधार पर किया गया है। इसके मुताबिक, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाएं अधिक स्थिर और सुरक्षित रोजगार की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि, स्वरोजगार के मोर्चे पर यह बदलाव कम है। यह पैटर्न शहरी इलाकों में ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखता है, जहां महिलाओं के घर की मुखिया होने का संबंध नियमित वेतन वाले रोजगार में 10 फीसदी की बढ़ोतरी और स्वरोजगार में 8% की गिरावट से है।

शिक्षा से ही बदलेगी असली तस्वीर

शिक्षा सबसे पहले महिलाओं को अनौपचारिक श्रम से बाहर निकालती है और एक निश्चित स्तर के बाद उन्हें नियमित रोजगार में शामिल करती है। जो महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उनके अनौपचारिक मजदूरी में शामिल होने की संभावना 0.21% है। जिन महिलाओं ने मिडिल से सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा हासिल की है, उनमें यह घटकर 0.12% रह जाती है। निर्णायक बदलाव हायर सेकेंडरी और उससे ऊपर के स्तर पर आता है, जहां नियमित वेतन वाले रोजगार में महिलाओं के शामिल होने की संभावना बढ़कर 0.44% हो जाती है और अनौपचारिक मजदूरी में जाने की स्थिति घटकर 0.03% रह जाती है। स्वरोजगार का चलन कम हो जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाओं के लिए स्थायी व वेतन वाले रोजगार पैदा करने के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना बेहद जरूरी है।

स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य... सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्ट में दाखिल जमानत मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कई हाई कोर्ट्स में दाखिल जमानत की अर्जियों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए कई सुझाव दिए। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसे मामलों की लिस्टिंग और सुनवाई के लिए लंबित केसों और बार-बार होने वाली देरी पर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच एक केस (सनी चौहान बनाम पंजाब राज्य) की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पहले पूरे देश के हाई कोर्ट्स से लंबित जमानत अर्जियों के बारे में जानकारी मांगी थी।

यह देखते हुए कि अधिकतर हाई कोर्ट्स ने जरूरी डेटा दे दिया था और जमानत के मामलों के समय पर निपटारे के लिए पहल की थी, कोर्ट ने फिर भी कुछ अधिकार क्षेत्रों, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता जताई। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, "हालांकि जानकारी आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन हम इसे आदेश में शामिल करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि ज्यादातर हाई कोर्ट्स ने समय पर मामले की निपटारे के लिए पहल की है।"

इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है।" भले ही जज "एक दिन में सैकड़ों केसों" की सुनवाई करते हों। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रशासनिक समिति पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी कि वे एक ऐसा व्यवस्था बनाएं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर जमानत अर्जी के लिए सुनवाई की एक तय तारीख तय हो। इसके लिए "न्यायिक संसाधनों के मिलाने" का सुझाव भी दिया और निर्देश दिया कि जमानत के मामलों को कॉज़ लिस्ट में प्राथमिकता दी जाए।

बेंच ने यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट में भी इसी तरह की व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जहां "जमानत के मामले कभी-कभी महीनों तक टल जाते हैं।" इसी तरह कोर्ट ने कहा कि एक साल पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 63,000 से अधिक जमानत अर्जियों का लंबित होने से "चिंताजनक स्थिति" बन गई थी, साथ ही यह उम्मीद भी जताई कि तब से काफी संख्या में मामलों का निपटारा हो गया होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि उसकी टिप्पणियों को किसी भी हाई कोर्ट की आलोचना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, कोर्ट का कहना है कि ये निर्देश व्यवस्था की कार्यक्षमता को मजबूत करने के मकसद से दिए गए थे।

विपक्ष की क्या मजबूरी , महिला आरक्षण से क्यों दूरी

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भाजपा की महिला जन आक्रोश के तहत धरना प्रदर्शन में बोलते हुए जिला मंत्री अंशु कुशवाहा ने कहा कि नारी शक्ति ने हमेशा देश को दिशा दी है, लेकिन जब बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे हक की आती है, तो देरी क्यों? संसद में हमारी भागीदारी हमारा अधिकार है, कोई खैरात नहीं आज की ये खामोश गूँज कल के बदलाव की आहट है जब तक अधिकार नहीं तब तक धरना के माध्यम से उनका विरोध करते रहेंगे घर चलाने वाली नारी अब देश की नीतियां भी तय करेगी नारी वंदन अधिनियम के पास होने में हो रही देरी सिर्फ एक कानून की देरी नहीं, बल्कि करोड़ों महिलाओं के सपनों की देरी है सड़कों पर उतरी ये महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रागिनी सिंह ने कहा कि यह बिल देश की उस सरकार की इच्छाशक्ति का परिणाम है आज हम यहाँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर इस धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज उठाने आए हैं दशकों से भारतीय राजनीति में हमारी माताओं-बहनों को उनका हक देने की बातें तो होती थीं, लेकिन नियत साफ नहीं थी। लेकिन बहनों, अफसोस की बात देखिए! जो विपक्ष खुद को जनता का हितैषी बताता है, उसी विपक्ष ने इस बिल की राह में रोड़े अटकाने का काम किया। जब संसद में माँ भारती की बेटियों को उनका अधिकार दिया जा रहा था, तब विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे थे, कमियाँ निकाल रहे थे और इसे रोकने की साजिश रचे। जिला उपाध्यक्ष राखी सिंह ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ उन विपक्षी दलों से क्या इस देश की बेटी नीति-निर्धारण में हिस्सा लेने के काबिल नहीं है? क्या आपको डर है कि अगर महिलाएँ सदन में पहुँच गईं, तो आपकी परिवारवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी विपक्ष का यह विरोध केवल एक बिल का विरोध नहीं है, बल्कि यह देश की आधी आबादी के सपनों का विरोध है। यह उस हर उस महिला का अपमान है जो समाज में बराबरी का हक चाहती है। इन्होंने सालों तक इस बिल को फाइलों में दबाए रखा और आज जब यह हकीकत बना है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अंजना सिंह ने कहा कि बहनों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है जो लोग आज सड़कों पर आकर झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, संसद में उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है।

गोरखपुर में प्रिंसिपल ने स्कूल में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में किया गर्लफ्रेंड का जिक्र

... मौत से पहले व्हाट्सएप पर भी शेयर किया स्टेटस

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज परिसर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले प्रिंसिपल ने एक सुसाइड नोट लिखा और वीडियो बनाकर उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी प्रेमिका और उसके परिवार को मौत का जिम्मेदार बताया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला जिल के चौरी-चौरा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के पूर्व प्रधान दिनेश सिंह का गांव के बाहर यदुवंश सिंह पार्वती देवी इंटर कॉलेज है। कॉलेज के प्रबंधक दिनेश सिंह हैं, जबकि उनके बड़े बेटे 30 वर्षीय धीरज सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल थे। शनिवार को धीरज रोज की तरह कॉलेज गए थे, लेकिन रविवार सुबह तक घर वापस नहीं लौटे।

परिजनों के अनुसार, छोटा भाई सत्य प्रकाश सिंह जब उन्हें बुलाने कॉलेज पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर धीरज सिंह का शव पंखे की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता मिला। यह नजारा देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

कॉलेज की टीचर से था अफेयर

पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक ने कॉलेज की एक शिक्षिका से प्रेम संबंध होने का जिक्र किया है। उसने लिखा कि दोनों परिवार पहले शादी के लिए राजी थे, लेकिन बाद में युवती और उसके परिवार ने शादी से इंकार कर दिया। सुसाइड नोट में आरोप लगाया गया कि युवती लगातार संबंध बनाती रही, लेकिन बाद में उसे खुदकुशी करने तक की धमकी देने लगी।

परिजन ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक के भाई ने बताया कि युवती का परिवार उनके भाई को जान से मारने की धमकी भी देता था, जिससे वह काफी तनाव में थे। क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सुसाइड नोट, वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

पश्चिम में आसपा बिगाड़ सकती है दिग्गजों का खेल, इस 'भाग्यशाली' सीट से चंद्रशेखर आजाद ठोक सकते हैं ताल

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए मेरठ को प्रचार का केंद्र बनाएंगे।

चर्चा है कि पार्टी जिले की सभी सातों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चंद्रशेखर खुद हस्तिनापुर से ताल ठोंक सकते हैं। वहीं, सरधना से शाहजेब रसूलपुर और मेरठ शहर विधानसभा से बदर अली के नामों की सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। हस्तिनापुर (सुरक्षित) सीट हमेशा से ही यूपी की राजनीति में सत्ता की कुंजी मानी जाती रही है। कहा जाता है कि यहां से जीतने वाली पार्टी ही लखनऊ की गद्दी पर बैठती है। चंद्रशेखर आजाद के यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा के पीछे गहरी रणनीतिक वजहें हैं।मेरठ और आसपास के जिलों में दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता बसपा के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। सबसे अधिक नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होने की आशंका है। पश्चिमी यूपी में दलित मतदाता विशेषकर युवा वर्ग अब चंद्रशेखर को एक आक्रामक विकल्प के रूप में देख रहा है। अगर दलित वोट बंटता है तो बसपा के लिए मुश्किल होगी।

भाजपा पर भी पड़ेगा असर

इन सीटों पर आसपा मजबूती से लड़ती है तो सपा का पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला मेरठ में दरक सकता है। दरअसल, सपा को उम्मीद है कि दलित वोट भाजपा के खिलाफ उनके पाले में आ सकता है, लेकिन चंद्रशेखर के अलग लड़ने से दलित वोटों का काफी हिस्सा आसपा की ओर शिफ्ट हो सकता है। इसका असर भाजपा पर भी पड़ेगा। भाजपा भी दलितों को अपना वोट बैंक मान रही है। कैंट से संजीव पाल दावा कर रहे हैं, जबकि मेरठ दक्षिण से नूर सैफी का नाम चल रहा है। किठौर और सिवालखास से भी दावेदारों के नाम मांगे जा रहे हैं। फिलहाल आसपा के उम्मीदवारों की चर्चा ने बड़े दलों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है।

मुस्लिम मतों में बिखराव की आशंका

रणनीतिकार मानते हैं कि सरधना सीट से दावेदार शाहजेब रसूलपुर की उम्मीदवारी मुस्लिम वोटों में बिखराव पैदा कर सकती है। इसका सीधा असर सपा के समीकरणों पर पड़ेगा। सरधना से सपा के अतुल प्रधान विधायक हैं।

शहर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला

वहीं, मेरठ शहर विधानसभा सीट के दावेदार बदर अली की स्थानीय स्तर पर पहचान और उनके साथ जुड़ रहे युवाओं की टोली शहर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है। यहां मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा है। यहां पारंपरिक रूप से सपा और भाजपा के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन बदर अली की मौजूदगी इसे दिलचस्प बना सकती है। शहर सीट से सपा के रफीक अंसारी विधायक हैं। दक्षिण से पिछली बार सपा से आदिल चौधरी चुनाव लड़े थे और उन्हें भाजपा के सोमेंद्र तोमर को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार नूर सैफी की उम्मीदवारी इस सीट के भी समीकरण बदल सकती है।

भीड़ में घुसी बेकाबू कार, पांच श्रद्धालु घायल

जौनपुर। जलालपुर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर के समीप सोमवार को एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसी। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार चालक का नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत घायलों की मदद में जुट गए।सूचना मिलते ही जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल अरविंद राजभर को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।

बोर्ड की बैठक का सभासदों ने किया विरोध

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नगर पंचायत कजगांव कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में सभासदों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान की अध्यक्षता में उक्त नगर पंचायत बोर्ड की बैठक चल रही थी कि इसी दौरान तमाम सभासदों ने बोर्ड बैठक का विरोध करने लगे।सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों में कार्य हो रहा हैं तथा बाकी वार्डों में कार्य कोई कार्य नही हो रहा है।उन्होंने अध्यक्ष पर अन्य वार्डो के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। सभासदों ने यह भी कहा कि जब हम सभी लोग किसी कार्य को कराने के लिए कहते हैं तो उसको नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। सभासदों ने यह भी कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा खुले आम मनमानी जमकर किया जाता है। और नगर पंचायत में कराए जा रहे तमाम विकास कार्यों में खुलेआम भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार भी व्याप्त है।भ्रष्टाचार का विरोध जब हम सभी सभासद करते हैं तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। सभासद सुनील विश्वकर्मा, आकाश सिंह अरविन्द प्रजापति, आलोक मौर्य,इकबाल अन्सारी, अखिलेश यादव,इजलाश यादव,सुरज कन्नौजिया,आदि रहे।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर निकाली कलश यात्रा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत जनपद में श्रद्धा, आस्था एवं सांस्कृतिक चेतना से ओत-प्रोत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन., मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी द्वय अजय अंबष्ट, परमानन्द झा सहित अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर डाक बंगला चैराहा होते हुए पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर तक पहुँची, जहां पर मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में अत्यंत उत्साह एवं भक्ति भाव देखने को मिला। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर पारंपरिक एवं धार्मिक वातावरण को और अधिक आकर्षक बनाया। "हर-हर महादेव" एवं भगवान शिव के जयघोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं एवं आमजनमानस द्वारा पुष्पवर्षा कर स्वागत भी किया गया। कलश यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, छात्र-छात्राएं शिक्षक एवं आमजन उपस्थित रहे। यात्रा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा एवं धार्मिक एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए थे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायतों में भी शिव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा शिवालयों में मंत्रोच्चार, ओंकार जाप, महाआरती रुद्राभिषेक, दीपोत्सव तथा भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ इसमें स्थानीय समुदाय द्वारा जनभागीदारी की गई। साथ ही विभिन्न विद्यालयों में पेंटिंग, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। संचालन शिक्षिका नूपुर श्रीवास्तव द्वारा किया गया। विभिन्न अधिकारीगण, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

यूपी में हैवान बना देवर : गर्भवती भाभी को काटा, जला था पेट का हिस्सा, एक घंटे तक लाश के पास फावड़े लिए खड़ा रहा

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर के नानौता कस्बे की नाइयों वाली गली में गर्भवती महिला की हत्या के बाद आरोपी युवक हाथ में एक घंटे तक फावड़ा लेकर शव के पास खड़ा रहा, लेकिन पुलिस उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोग लगातार आरोपी को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह हाथ में फावड़ा लिए आक्रामक होकर शव के पास खड़ा रहा।

माहौल इतना भयावह था कि आसपास के लोग दूर ही खड़े रहे। काफी जद्दोजहद के बाद पूर्व चेयरमैन के भाई ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।

बताया जा रहा है कि आरोपी शुरू से ही परिवार में हुए प्रेम विवाह का विरोध करता था। शादी के बाद से वह इस रिश्ते को लेकर नाराज चल रहा था। हालांकि, बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि उसकी नाराजगी अपने भाई से थी तो उसने हमला अपनी गर्भवती भाभी पर क्यों किया। इसी सवाल को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। घटना के बाद से दहशत और गुस्से का माहौल है।

गले पर कट के निशान, जला हुआ है पेट

मृतका की मां का आरोप है कि सना के गले पर कट के निशान हैं और पेट का कुछ हिस्सा जला हुआ है। पिता आशिक का आरोप है कि सना की हत्या में सभी ससुराल वाले शामिल हैं। हत्या के बाद सास और ननद पहले ही प्लानिंग के तहत कहीं चली गई थीं और पति भी साजिश के तहत ही थाने पहुंचा है। वह अपने भाई को मोहरा बनाकर पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है।

घर भागकर थाने पहुंच की थी शादी

सना और सलमान के घर आमने सामने हैं। दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब सात माह पहले दोनों घर से भाग कर थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस ने विवाह कराने और सुरक्षा देने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया था। कस्बे के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में सना को सलमान के साथ भेज दिया गया था। तभी से सना का अपने मायके आना जाना बंद था।

प्रेम विवाह से नाराज देवर ने की गर्भवती भाभी की हत्या

सहारनपुर के नानौता में नाइयों वाली गली में रविवार रात आठ बजे प्रेम विवाह के कारण नाराज देवर आमिर ने अपनी गर्भवती भाभी सना नाज (23) की हत्या कर दी। सना नाज के गले पर धारदार हथियार के वार के निशान मिले। शरीर पर जगह-जगह जले होने के भी निशान मिले हैं।

हत्या के बाद आरोपी काफी देर तक शव के पास फावड़ा लेकर खड़ा रहा और पुलिस सहित किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। किसी तरह उसे पकड़ा गया। महिला के पति और देवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने बताया कि नाई बिरादरी की सना नाज ने कुछ माह पहले राजपूत बिरादरी के पड़ोसी युवक सलमान राव से प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से परिवार में तनाव की स्थिति थी। रविवार की शाम सना घर में अकेली थी। इसी दौरान देवर आमिर से उसका विवाद हो गया। आमिर ने फावड़ा उठाकर सना पर वार कर दिए।

पुलिस भी कुछ देर तक आरोपी के आक्रामक रवैये के चलते अंदर नहीं जा सकी। इसी बीच पूर्व चेयरमैन अफजाल खान के भाई निसार खान ने आरोपी को पकड़ लिया। निसार के हाथ में फावड़ा लगने से हल्की चोट लगी है। आरोपी चंडीगढ़ में फल बेचने का काम करता है। पुलिस प्रेम विवाह, पारिवारिक विवाद और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सना चार-पांच माह की गर्भवती थी।

'झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में...', सोशल मीडिया पर आमने-सामने आए पहलवान विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण

आर्यावर्त संवाददाता

गोंडा. पहलवान विनेश फोगाट और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। नंदिनी नगर में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब इशारों और शेरो-शायरी तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर दोनों के आरोप-प्रत्यारोप की खेल व राजनीतिक जगत में चर्चा हो रही है।

पहलवान विनेश फोगाट ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा की है। इसमें लिखा, 'जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जमाना ढूंढ़ता है खामी मेरे किरदार में... जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं किसी तलवार में...!' विनेश की इस पोस्ट को उनके समर्थक संघर्ष और आत्मसम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। चर्चा है कि यह पोस्ट गोंडा में रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता और उससे जुड़े घटनाक्रमों की ओर इशारा कर रही है।

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी दी प्रतिक्रिया

विनेश की इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक शेर साझा करते हुए लिखा, 'शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है।' सोशल मीडिया यूजर इसे विनेश की पोस्ट का जवाब मान रहे हैं। हालांकि, दोनों ने सीधे तौर पर एक-दूसरे का नाम नहीं लिया है, लेकिन समय और संदर्भ को देखते हुए इसे सीधा मुकाबला माना जा रहा है।

विवाद की जड़ 10 से 12 मई तक नंदिनी नगर में होने वाली सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता है। हाल ही में विनेश फोगाट ने इस आयोजन स्थल को लेकर अपनी असहजता जताई थी। इसके बाद पूर्व सांसद ने स्पष्ट किया था कि इस प्रतियोगिता से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा था कि आयोजन भारतीय कुश्ती संघ की ओर से कराया जा रहा है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।

विनेश ने जवाब नहीं दिया तो लगेगा प्रतिबंध : संजय सिंह

भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट ने अनुशासनहीनता के नोटिस का समय पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उन पर प्रतिबंध लग सकता है। गोंडा में नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को आयोजित ओपन सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर आए संजय सिंह ने कहा कि विनेश हर बात पर आरोप लगाने की आदी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि विनेश के प्रतियोगिता में आने की बात कहने पर सुरक्षित लाने, मुकाबला कराने व वापस छोड़ने की पूरी जिम्मेदारी ली गई थी।

अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में देशभर से खिलाड़ी हिस्सा लेने आए हैं। इनमें हरियाणा की महिला पहलवानों की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि 2023 के आंदोलन से कुश्ती को बड़ा नुकसान हुआ। ओलंपिक में चार पदक का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ एक पदक ही मिला। आंदोलन का असर तैयारी पर भी पड़ा। अब 2024 में बेटियों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है और कुश्ती फिर पटरी पर लौट आई है।संजय सिंह ने बताया कि 2028 ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत को चार से पांच पदक मिलने की उम्मीद है। देशविरोधी कुछ ताकतें फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकती हैं।

बृजभूषण शरण सिंह और विनेश के बीच सोशल मीडिया पर शायरी पोस्ट करने को लेकर संजय सिंह ने कोई टिप्पणी नहीं की। वह सिर्फ इतना बोले कि बृजभूषण शायरी के बादशाह हैं। जवाब देने में पूर्वांचल में उनका मुकाबला नहीं है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, वह उनका व्यक्तिगत मामला है।

संजय सिंह ने कहा कि नंदिनी नगर स्टेडियम जैसी सुविधाएं देश में कहीं नहीं हैं। प्रतियोगिता में 28 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती में करीब 600 पहलवान मैदान में हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत हरियाणा से हैं। रैंकिंग सीरीज का मकसद नए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तरह आगे बढ़ने के लिए मंच देना है।

दुल्हा हत्याकाण्ड में तीन पर एक लाख का इनाम

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। दूल्हे आजाद बिंद हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपियों की तलाश में अब स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भी शामिल हो गई है। इन तीनों आरोपितों पर इनाम की राशि 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। फरार आरोपितों में आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के चिकसांवा निवासी प्रदीप बिंद, खेतासराय थाना क्षेत्र के सौंधी निवासी रवि यादव और सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जपटापुर के भोले राजभर शामिल हैं। एसआइटी के साथ-साथ पुलिस की दस टीमें भी इनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। हालांकि, मुख्य आरोपित अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ ने इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस को आरोपितों को शरण देने वालों के बारे में भी अहम सुराग मिले हैं। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पहला मौका है जब किसी हत्याकांड के फरार आरोपितों पर इतनी जल्दी इनाम की राशि बढ़ाई गई है। ज्ञात हो कि यह घटना 1 मई की रात को हुई थी। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बड़ठर गांव निवासी 24 वर्षीय आजाद बिंद का विवाह खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर (जमदहो) निवासी मोरख नाथ बिंद की पुत्री सोनी बिंद के साथ तय हुआ था। बारात लेकर जाते समय, रात में लगभग सात किलोमीटर दूर खेतासराय के बादशाही बाजार के पास बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उनकी कार रोक ली। हमलावरों ने आजाद बिंद को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। आजाद बिंद के पिता राम लखन बिंद की तहरीर पर तीनों नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

तकनीक समय की तरह, इसके साथ नहीं चले तो पिछड़ जाएंगे, सीएम योगी ने दी युवाओं को नसीहत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीक की तुलना समय से की। सीएम योगी ने 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' के मौके पर युवाओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि तकनीक और समय एक ही जैसे हैं और जो इसके साथ नहीं चला वह पिछड़ जाएगा। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य के लोगों के लिए पत्र शेयर किया। उन्होंने कहा कि तकनीक केवल विकास का जरिया ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। उन्होंने लिखा कि मेरे युवा साथियों, तकनीक समय की तरह है। तकनीक के साथ नहीं चलना, समय से पिछड़ जाना है। तकनीक के साथ चलने का मतलब सुदृढ़ वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने युवाओं से कहा कि नई-नई तकनीक सीखें, नवाचार अपनाएं एवं आत्मनिर्भर राज्य के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

सीएम योगी ने ये लेटर को 'योगी की पाती' शीर्षक से लिखा। सीएम ने लिखा कि हर साल 11 मई को 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' मनाया जाता है लेकिन ये दिन यूं ही नहीं चुना गया। उन्होंने लिखा कि 1998 में इसी दिन पोखरण में 'ऑपरेशन शक्ति' के अंतर्गत भारत ने तीन सफल परमाणु परीक्षण कर विश्व को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा, तकनीकी आत्मविश्वास और राष्ट्रीय सामर्थ्य का बोध कराया। इसी दिन स्वदेशी विमान 'हंस-3' ने सफल उड़ान भरी, तो स्वदेशी 'त्रिशूल' मिसाइल का परीक्षण भी हुआ। तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है।

140 करोड़ भारतीयों को ग र्व

सीएम योगी ने पत्र में बताया कि आज तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर खेत-खलिहान तक पहुंच गई है और इससे जनजीवन सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन में खुद से गणना हो जाने की सुविधा इसी तकनीक का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री ने पत्र में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के सपूत शुभांशु शुक्ला ने बीते सालों में सफल अंतरिक्ष उड़ान से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया, तो यह तकनीक का ही चमत्कार है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सीएम योगी ने लेटर में बताया कि इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड के मूलमंत्र के साथ हमारी सरकार ड्रोन, क्वांटम, ग्रीन हाइड्रोजन एवं मेड-टेक के क्षेत्र में प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश को देश का 'डीप टेक कॅपिटल' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीक आधारित विकास की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश आज आईटी पार्क, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। यहां ब्रह्मोस मिसाइल तक बन रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे नई-नई तकनीक सीखें, नवाचार अपनाएं एवं आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं और यही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

नैक और वैश्विक मानकों पर होगा फोकस, योगी सरकार ने तैयार किया रोडमैप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में अब नया लक्ष्य तय किया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों को नैक (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल) में ए , ए और ए ग्रेड तक पहुंचाने के बाद अब सरकार डिग्री कॉलेजों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग दिलाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों को विशेष कार्यशालाओं के जरिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सोमवार को विधानसभा में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार अब केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिग्री कॉलेजों को भी उत्कृष्टता के नए मानकों तक पहुंचाने पर फोकस कर रही है। कॉलेजों में गुणवत्ता सुधार, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने, छात्र संख्या बढ़ाने और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को केवल सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला राज्य बनाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अग्रणी केंद्र बनाना है। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। पहले अधिकांश विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग में बी या बी-प्लस ग्रेड तक सीमित थे, लेकिन अब प्रदेश के सात विश्वविद्यालय ए ग्रेड हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा चार विश्वविद्यालय ए और दो विश्वविद्यालय ए ग्रेड में पहुंच गए हैं।

मदर्स डे के उपलक्ष्य में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

लखनऊ मेट्रो एवं डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मदर्स डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (लखनऊ मेट्रो) एवं डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ लखनऊ के संयुक्त सहयोग से हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एक विशेष सांस्कृतिक एवं नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 25 प्रतिभाशाली बच्चों एवं कलाकारों ने नृत्य, संगीत, कविता एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मातृत्व के प्रति सम्मान एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश दिया।

कार्यक्रम में तनिष्क बंसल, शिक्षा अग्रवाल, रजत पांडेय, सांवी तिवारी, मोहलक्षिका सिंह, नेविका सिंह, श्रेयाशी विश्वकर्मा, अनुप्रिया सिंह, गार्गी द्विवेदी, योग्या वर्मा, फहीम खान, उदिशा सिंह, रिया मौर्य, अश्वनी यादव, शेखर श्रीवास्तव, रिदम गुप्ता, आदित्य गुप्ता, वर्षा मिश्रा, ऋचा मिश्रा,लावण्या काबरा, गौरवी बंसल, ध्वनि मिश्रा एवं पीयूष बाबा सहित अनेक प्रतिभागियों ने आकर्षक प्रस्तुतियाँ दीं।

गार्गी द्विवेदी की प्रस्तुति ने मोहा मन : इस समारोह के दौरान मुख्य आकर्षण बाल नृत्यांगन गार्गी द्विवेदी की नृत्य प्रस्तुति रही। गार्गी द्विवेदी ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली नृत्य प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोहा लिया। बता दें कि गार्गी विशेष रूप से अपने कथक नृत्य और भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं।

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती नवमिता दास, श्रीमती सुरभि बंसल, श्रीमती ऋचा अग्रवाल, श्रीमती दीपा श्रीवास्तव, श्रीमती अनुभा जोशी एवं श्रीमती कीर्तिका वर्मा ने गीत, कविता एवं ग़ज़ल प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भावनात्मक एवं सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर डॉ. नीरज जैन, डॉ. कीर्ति विक्रम सिंह,रीजनल डायरेक्टर , इग्नू,मेट्रो के ज्वाइन जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा एवं सुदीप सिंह, के. बी. पंत, अधिवक्ता कमल जोशी, सदन यादव, अर्जुन अवॉर्डी श्रीमती रचना गोविल, अधिवक्ता के.सी. पंत सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं अभिभावक उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना तथा समाज में सकारात्मक एवं पारिवारिक वातावरण को प्रोत्साहित करना है।

यूपी में ब्राह्मण समाज काफी असुरक्षित... मायावती ने कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी को घेरा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को ब्राह्मणों की चिंता सता रही है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूपी में ब्राह्मण समाज यहां केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है। उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के एक युवा नेता पर जानलेवा हमला होने से हर तरफ एकबार फिर से कानून-व्यवस्था के साथ-साथ इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गयी है कि यूपी में ब्राह्मण समाज यहां केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है, जो अति-चिन्तनीय, जबकि बी।एस।पी। की रही सभी सरकारों में समाज के हर वर्ग के जान, माल व मजहब के साथ-साथ बेहतरीन कानून-व्यवस्था के तहत ब्राहमण समाज सहित समाज के सभी वर्गों को 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति व सिद्धान्त के अन्तर्गत न्याय और सुरक्षा दी गयी थी, जो कि सर्वविदित है। मायावती ने दूसरे पोस्ट में सहारनपुर में 9 मई दो बीघा जमीन विवाद में का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में ठाकुर-दलित के बीच दो बीघा जमीन को लेकर हुए जातीय संघर्ष के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि लालवाला गांव में अनुसूचित जाति और ठाकुर समाज के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर शनिवार को जमकर पथराव हुआ था। दोनों पक्षों के बीच चले संघर्ष में तीन महिलाओं समेत आठ लोग घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।

पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप

मायावती ने घटना के बाद दलित समाज ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई और लाठीचार्ज का आरोप लगाया। मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर अपने पदाधिकारियों के साथ गांव जाकर पीड़ित पक्ष से मिलने वाले थे। प्रशासन ने संभावित तनाव को देखते हुए उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। लालवाला गांव में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस दोनों पक्षों पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश कर रही है। विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्ष अपना - अपना दावा कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि जमीन उनकी आबादी की है। जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि जमीन उन्होंने पहले ही खरीदी है।

मायावती सोशल मीडिया X पर यूपी सरकार के मंत्रिमंडल पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल को घटाना-बढ़ाना व विस्तार आदि सत्ताधारी पार्टी का आन्तरिक राजनीतिक चिन्तन का मामला ज्यादा होता है और इसीलिये उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के कल हुये विस्तार के बारे में कुछ भी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, किन्तु कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आमजन के हित के साथ-साथ खासकर सर्वसमाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी एवं महिला सुरक्षा-सम्मान आदि पर पड़ता हुआ दिखना भी जरूर चाहिये, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बढ़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे।

आपका इंस्टा फ्रेंड ' सौरभ सिंह ' तो नहीं ? लखनऊ का शोएब हिंदू लड़कियों को ऐसे करता था टारगेट, फिर करता था ब्लैकमेल

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाला प्रेम जाल और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। गोंडा निवासी शोएब अख्तर नामक युवक पर आरोप है कि उसने सौरभ सिंह के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर हिंदू युवतियों और नाबालिग लड़कियों को पहले प्रेम के जाल में फंसाया। उनका शारीरिक शोषण किया और फिर अश्लील वीडियो-फोटो के आधार पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी शोएब अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके मोबाइल फोन से कई नाबालिग हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, शोएब सैरपुर थाना क्षेत्र के रैथा रोड पर एक सैलून चलाता है। पुलिस के मुताबिक, उसने सोशल मीडिया पर अपनी असली पहचान छिपाकर सौरभ सिंह नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। इसी प्रोफाइल के जरिए वह हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता, प्रेम जाल बिछाता और बाद में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। आरोपी कथित तौर पर लड़कियों की अश्लील फोटो और वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लेता था। इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर वह उन्हें ब्लैकमेल करता और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता था।

इस पूरे साजिश का खुलासा तब हुआ जब एक नाबालिग पीड़िता ने सैरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती बताते हुए शोएब के पूरे काले कारनामों का खुलासा किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच की जा रही है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शोएब ने अब तक कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया और क्या इस साजिश में उसके कोई साथी भी शामिल हैं। धर्मांतरण के एंगल की भी पुलिस जांच कर रही है।

अन्य पीड़िताओं से संपर्क की कोशिश

पुलिस अब शोएब के फोन में मिले नंबरों, चैट्स और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर अन्य संभावित पीड़िताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या आरोपी अकेला था या कोई बड़े गिरोह का हिस्सा है।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश– रात 10 बजे के बाद तेज शोर रोकें अफसर, तय सीमा से अधिक शोर न हो

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आम लोगों समेत बच्चों व बुजुर्गों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद शादी, विवाह व अन्य समारोहों में होने वाले तेज शोर को सख्ती से रोकने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस, नगर निगम और एलडीए को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत समुचित कार्रवाई करने को कहा है।

अदालत ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पार्कों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों का विवरण तैयार कर उन्हें उत्तर प्रदेश पार्क, खेल मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत तैयार की जाने वाली सरकारी सूची में शामिल करें। कोर्ट ने उन्हें ऐसे स्थानों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का भी पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी 18 मंडलों के कमिश्नर और सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का सर्वे करें और उन्हें सरकारी सूची में शामिल करें। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश धर्मपाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने शहर के जनेश्वर मिश्रा पार्क के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधियों के दौरान तेज शोर होने की जन समस्या का भी संज्ञान लिया। कहा कि अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सूचीबद्ध पार्क, खेल के मैदान या खुले स्थानों का उपयोग, उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके लिए उनका उपयोग 1975 में अधिनियम लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा था, जब तक कि इसके लिए निर्धारित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति न ली जाए।

हाईकोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को कहा है कि जनेश्वर मिश्र पार्क समेत अन्य पार्कों, खेल के मैदानों, खुली जगहों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करने पर पुनर्विचार करें। अदालत ने टिप्पणी की कि पार्क में रहने वाले पक्षियों और अन्य जीवों पर ऐसी गतिविधियों का बुरा असर पड़ता है और यह पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। साथ ही अदालत ने खास तौर पर शहर के रिहायशी इलाकों समेत पार्कों में आयोजित होने वाले समारोहों में तय सीमा से अधिक शोर होने पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।

मौसम विभाग का अनुमान, गरज चमक के साथ इन जिलों में होगा वज्रपात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात तथा तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा सोमवार को जारी प्रभाव आधारित पूर्वानुमान एवं चेतावनी के अनुसार 11 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 12 मई को पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

यूपी कैबिनेट विस्तार: नए चेहरों से भविष्य पर नजर, योगी ने हिंदुत्व से साधा जातीय गणित, अखिलेश के पीडीए की काट

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। यूपी में करीब तीन महीने के चिंतन-मंथन के बाद सारे कयासों पर विराम लगाते हुए आखिरकार योगी-दो के कैबिनेट का दूसरा विस्तार संपन्न हो गया। इससे सरकार और भाजपा संगठन ने जहां जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है, वहीं, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से हिंदुत्व एजेंडे.के जरिए जातीय गणित को भी साधा है। वहीं, इस संक्षिप्त विस्तार के सहारे में भाजपा सपा के पीडीए फार्मूला की काट तैयार कर विपक्ष के लिए तगड़ी घेरेबंदी की जमीन भी तैयार करेगी।

नए सदस्यों को शामिल करते हुए पूरे मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो पाएंगे कि भाजपा सत्ताईस के संग्राम में जातियों की एकजुटता के सहारे हिंदुत्व की एकता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने का भी संकेत छिपा है। पहली कोशिश जातियों की गणित साधते हुए हिंदुत्व को मजबूती देने की ही दिख रही। बिना कोई बड़ा उलटफेर किए जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जिन चेहरों को शामिल किया गया है वह बताता है कि भाजपा नेतृत्व प्रदेश में विधानसभा के आगामी चुनाव में भरोसे और एकजुटता के संदेश के साथ उतरने का फैसला किया है।

कुछ मंत्रियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रही हैं लेकिन पहले से मंत्रिमंडल में मौजूद किसी मंत्री को अगर छेड़ा नहीं गया है तो उसकी बड़ी वजह यही है कि भाजपा ऐसा करके यह संदेश देने की कोशिश किया है कि मंत्रिमंडल में कुछ गड़बड़ नहीं है और विपक्ष के ऐसे सभी आरोप गलत है।

भाजपा ने विस्तार के जरिये यह भी संदेश देने की कोशिश है कि नए चेहरों के जरिए जहां पीडीए की काट तैयार की गई है, वहीं, मनोज पाण्डेय को शामिल कर ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। साथ ही अगड़ों के सम्मान के ध्यान का संदेश दिया गया है।

भूपेन्द्र चौधरी, कैलाश राजपूत तथा हंसराज विश्वकर्मा को शामिल करके एवं अजीत सिंह पाल व सोमेन्द्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री के रूप में पदोन्नति देकर भाजपा में पिछड़ों के सम्मानजनक प्रतिनिधित्व और उनके सरोकारों के प्रति सम्मान का संदेश दिया गया है। साथ ही कृष्णा पासवान और सुरेन्द्र दिलेर को मंत्री बनाकर दलित वर्ग की भी हिस्सेदारी का समुचित ध्यान रखने का संदेश दिया गया है । इस सबसे अधिक यह विस्तार भाजपा की 'बंटोगे तो कटोगे' की नीति को आगे बढ़ाता दिख रहा है। इस विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने से अधिक हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी दिख रही है।

25 ओबीसी व 10 दलित चेहरे

चुनावी लिहाज से हुए विस्तार में योगी कैबिनेट में पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। विस्तार में पिछड़ी जाति के तीन सदस्यों को शामिल करने के बाद इनकी संख्या अब 25 और दलित समाज के मंत्रियों की संख्या 10 हो गई है।

60 सदस्यीय कैबिनेट में अब सामान्य वर्ग के 21, अल्पसंख्यक वर्ग के 2 व अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक मंत्री हो गए हैं।

मंत्रिपरिषद का कोटा पूरा

दूसरे विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद का कोटा पूरा हो गया। 403 सदस्यीय विधानसभा में 15 फीसदी के नियम के तहत सीएम के अलावा 60 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में छह सीटें अरसे से खाली थीं।

मार्च, 2024 में कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ था। मंत्रिमंडल में सीएम व डिप्टी सीएम के अलावा 20 कैबिनेट मंत्री हैं। 16 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 21 राज्यमंत्री हैं।

कैबिनेट विस्तार में अखिलेश के पीडीए की काट

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव से ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का दांव चल रहे हैं। माना जा रहा है कि ताजा विस्तार में पिछड़े और दलित समुदाय के 4 सदस्यों को शामिल कर अखिलेश के पीडीए की धार कुंद करने की रणनीति है। टीम योगी में आधे से अधिक मंत्रियों का इन्हीं दोनों वर्गों से होना भी दिखाता है कि भाजपा पीडीए को गंभीरता से ले रही है और कोई चूक नहीं करना चाहती।

अखिलेश ने कहा, जब 9 साल में भाजपा सरकार प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो आखिरी के 9 महीनों में ये मंत्री क्या करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा सरकार में पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है।

नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई दी है।

उन्होंने लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राष्ट्र प्रथम के भाव से सभी मंत्री जनसेवा और सुशासन के संकल्पों के साथ उप्र के विकास यात्रा को नई गति प्रदान करेंगे। सीएम ने सभी नए मंत्रियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

भाजपा को परखने के औजार बदलने होंगे

भारतीय जनता पार्टी की बंगाल जीत ने केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान आकर्षित किया है। सभी अपने-अपने मापदण्डों पर इस चुनाव परिणाम को परख रहे हैं परन्तु पुराने ढर्रों पर चलते हुए फिर से गलती पर गलती दोहराते लगते हैं। यहां के विपक्ष की मानें तो यह एसआईआर के प्रयोग से निकला विजयमार्ग है तो विदेशी विश्लेषक फिर से जिंगल बैल जिंदल बैल की तरज पर साम्प्रदायिकता का गीत गाने लगे हैं। इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि भाजपा ने कहीं पहली बार पांव जमाए हैं, कहीं वह फिर से सत्ता में आई है तो कहीं उसने अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर केरल जैसे राज्य में वामपंथी दलों को भाजपा के प्रभाव के डर से अयप्पा के दर्शन करने पड़ें, भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बंजर कहे जाने वाले बंगाल में कमल की फसल लहलाने लगे, द्रविड़ राजनीति के केंद्र तमिलनाडू में उसकी आहट सुनने लगे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोधी इस दल को गलत औजारों से परख रहे हैं। विरोधी भूलते हैं कि देश का मतदाता मदिहीन नहीं है, वह सुशासन व विकास को अपनी पसंद बनाता जा रहा है। अगर कोई दल संविधान के अनुरूप काम करते हुए जनता की पसंद बन रहा है तो विरोधियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी।

भाजपा केंद्र और बहुत से राज्यों में वर्षों से शासन में है। अंधविरोध के चरम पर जा कर भी शासन व संवैधानिक व्यवस्था के किसी मान्य मापदण्ड पर विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मुद्दा तराश नहीं पाया है जो जनता को भी मान्य हो। यहां तक कि प्रधानमंत्री कई बार चुटकी ले चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष उनकी कोई तथ्यात्मक आलोचना करने में असफल रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता तक पहुंचते ही वैश्विक वैचारिक गलियारों में भी बेचैनी पैदा हो गई है। विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने भारत में लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर अचानक सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और अल जजीरा जैसे मंचों पर फिर से यह विमर्श तेजी से गढ़ा जाने लगा कि भारत हिन्दू राष्ट्रवाद की ऐसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां लोकतंत्र व बहुलता खतरे में है। विदेशी मीडिया में ज्यादा चर्चा बंगाल की है। सवाल यही है कि क्या चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या उस सियासी बदलाव की, जिसने दशकों पुराने वामपंथ और छद्मधर्मनिरपेक्षता के वैचारिक गढ़ को ध्वस्त कर दिया? जब भाजपा हारती है, तो विदेशी मीडिया भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की तारीफ करता है, पर जैसे ही वह निर्णायक जनादेश लेकर आती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया संदेह और संस्थागत संकट की भाषा में बदल जाती है। श्रेष्ठभावना से ग्रसित पश्चिमी जगत कहीं यह तो नहीं मानता कि भारतीय मतदाताओं में राजनीतिक समझ का अभाव है ?

राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक विचारक स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण पश्चिमी राष्ट्रवाद से सर्वदा विपरीत है। पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर यूरोपीय राजनीतिक अनुभवों के चश्मे से देखने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रवाद का अर्थ सत्ता विस्तार व नस्लीय वर्चस्व रहा है। जबकि भारत में राष्ट्रवाद सांस्कृतिक, सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक आत्मबोध से जुड़ा है। इसे विदेशी मीडिया समझ नहीं पाता। इसीलिए वो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सीधे अल्पसंख्यक-बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा की जीत को पश्चिम के विश्लेषकों ने लोकतांत्रिक परिवर्तन के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी कब्जे की तरह प्रस्तुत किया गया। एसआईआर पर अर्धसत्य दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिणामों के बाद वोट चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताया। विदेशी मीडिया ने इन आरोपों को लगभग बिना तथ्य जांचे ही अपने विमर्श का आधार बना लिया। विशेष रूप से एसआईआर को मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की साजिश के रूप में पेश किया गया, जबकि हटाए गए 91 लाख नामों में 63 प्रतिशत हिंदू मतदाता थे। बड़ी संख्या में नाम मृत, डुप्लिकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या फर्जी पाए गए थे। इसके बावजूद विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने केवल मुस्लिम वोट हटाए गए वाली जिद को प्रमुखता दी। देसी-विदेशी विश्लेषक यह भूल गए कि जिन 20 सीटों पर जाँच के बाद सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे, उनमें से ज्यादातर पर टीएमसी ने ही कब्जा जमाया है। इन सीटों में समशेरगंज, लालगोला, भगवानगोला, रघुनाथगंज, मटियाबुर्ज, सूती, मोथाबाड़ी, गोलपोखर, मालतीपुर, चोपड़ा, सुजापुर, राजारहाट न्यू टाउन और बशीरहाट उत्तर शामिल हैं। इन सभी 13 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली है। अन्य सीटों की बात करें तो फरक्का सीट पर सबसे ज्यादा 38,222 वोट काटे गए थे, लेकिन वहाँ से कॉन्ग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं भाजपा को जंगीपुर, रतुआ, करनदिघी, केतुग्राम, मानिकचक और मोंतेश्वर जैसी 6 सीटों पर जीत मिली।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक निर्णायक एवं ज़म्मिेदार शक्ति के रूप में उभरा

एयर वाइस मार्शल (डॉ.) अर्जुन सुब्रमण्यम (सेवानिवृत्त)

> इस संघर्ष की शुरुआत का उद्देश्य था - पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकवादी नेटवर्क के गढ़ पर सीधा हमला करना और अगर पाकिस्तान की सेना भारत के शुरुआती आतंकवाद-रोधी हमले का सैन्य जवाब देती है

यूक्रेन में जारी युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखने और मध्य-पूर्व के न युद्ध, न शांति के दलदल में फंसे होने के बावजूद, हाल के समय के दूसरे संघर्षों के मुकाबले ऑपरेशन सिंदूर को एक मानक अभियान के तौर पर देखना महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बातें थीं— सैन्य ताकत का तीव्र और नियंत्रित तरीके से निर्णायक इस्तेमाल, ताकि प्रबंधन करने योग्य संघर्ष-विस्तार में रहते हुए ऐसे रणनीतिक नतीजे हासिल किए जा सकें, जिनकी बाहर निकलने की रणनीति स्पष्ट हो और जो मोदी सरकार के राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। इस संघर्ष की शुरुआत का उद्देश्य था - पाकिस्तान के भारत-विरोधी आतंकवादी नेटवर्क के गढ़ पर सीधा हमला करना और अगर पाकिस्तान की सेना भारत के शुरुआती आतंकवाद-रोधी हमले का सैन्य जवाब देती है, तो उसे भारी नुकसान पहुंचाना। ये ऐसे बड़े लक्ष्य नहीं थे, जिनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर और हर तरफ सैन्य ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती। यह एक ज़म्मिेदार ताकत द्वारा, राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के बार-बार दोहराए जाने वाले कृत्यों को सज़ा देने के लिए चलाया गया एक सटीक, सक्रिय और संयमित प्रतिरोधी अभियान था।

हालांकि भारत ने 2019 में बालाकोट में आतंकवाद-रोधी अभियानों में आक्रामक हवाई शक्ति के इस्तेमाल का प्रयोग किया था, लेकिन इस बार जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों पर—जो क्रमशः बहावलपुर और मुरीदके में स्थित हैं—हमला करने की उसकी तत्परता ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जोखिम उठाने की एक नई प्रवृत्ति और संघर्ष को बढ़ाने की इच्छाशक्ति को उजागर किया। फिर भी, राजनीतिक स्तर पर सोच में पूरी स्पष्टता थी कि एक व्यापक संघर्ष भारत के हित में नहीं है, भले ही पाकिस्तान की सैन्य परिसंपत्तियों को और अधिक नुकसान पहुँचाने का सैन्य प्रलोभन मौजूद था। समझदारी और संयम, ज़म्मिेदार राज-काज और सैन्य अभियानों के दो ऐसे साथ-साथ चलने वाले पहलू हैं, जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छी तरह प्रदर्शित किया; खासकर इस मामले में कि उसने अपने हमलों के दौरान कोई भी अतिरिक्त नुकसान नहीं होने दिया और सैन्य श्रेष्ठता होने के बावजूद पाकिस्तान के युद्धविराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब पीछे मुड़कर देखने पर, एक लंबे और बड़े संघर्ष से मिलने वाले फ़ायदे, उसके संभावित आर्थिक और मानवीय नुकसानों के मुकाबले बहुत ही मामूली लगते हैं। चार दिनों के भीतर ही संघर्ष को समाप्त कर देने से जो सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हुई, उसने मध्य-पूर्व में चल रहे मौजूदा संघर्ष के दौरान भारत की आर्थिक सहनीयता में योगदान दिया है। दूसरी ओर, मध्य-पूर्व के संघर्ष में अमेरिका के 27 अरब डॉलर से भी ज़्यादा खर्च हो चुके हैं और इस संघर्ष का कोई अंत भी नज़र नहीं आ रहा है। भारत के मौजूदा उच्च रक्षा संगठन ने संघर्ष के दौरान अच्छी तरह काम किया। ऑपरेशन के नीति-निर्माण और तैयारी के चरण में केंद्रीकृत और निर्देशात्मक नियंत्रण का एक स्पष्ट मॉडल देखने को मिला; इसके पहले स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री थे, जबकि दूसरे स्तर पर सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख इसे समर्थन दे रहे थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेना प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों को स्पष्ट और ठोस रणनीतिक परिणाम बताए गए थे, जिसके बाद उन्हें एक व्यावहारिक कार्ययोजनाÓ तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी। भले ही हज़ारों सालों में युद्ध के स्वरूप में कई बदलाव आए हों, लेकिन कौटिल्य, सुन त्ज़ू, क्लॉज़विट्ज़ और लिडेल हार्ट जैसे प्राचीन और आधुनिक रणनीतिकारों द्वारा बताए गए युद्ध के अधिकांश मूल सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कुल मिलाकर, ऑपरेशन सिंदूर की भारत की सफलता ने तनाव बढ़ाने और प्रतिरोध करने की सीमाओं का विस्तार किया, भारत ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि इसने समय की कसौटी पर खरे उतरे युद्ध के कुछ सिद्धांतों और संकट के समय फ़ैसले लेने के तरीकों का पालन किया। इनमें से, लक्ष्य का चयन और उसे बनाए रखना, शक्ति का केंद्रीकरण, आक्रामक कार्रवाई, अचानक हमला, कमान की एकता, सुरक्षा, सरलता, मनोबल और अनुकूलनशीलता ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर और अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। परिचालन स्तर पर, भारत की उभरती हुई बहु-क्षेत्रीय सैन्य रणनीति के तलवार के रूप में आईएएफ का इस्तेमाल करने का फ़ैसला एक साहसी कदम था, जो आज के दौर के संघर्षों के बदलते स्वरूप को दिखाता है और जिस पर बारीकी से नज़र रखने और विश्लेषण करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की चीन से मिली वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने और उन्हें जाम करने के बाद, भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में घुसकर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान और पीओजेके में मौजूद 9 अहम आतंकवादी ठिकाने तबाह हो गए, और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख केंद्र नष्ट हो गए। 10 मई को, कुछ ही घंटों के भीतर, भारत ने अपने हमले का दायरा और बढ़ाया तथा 11 प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयरबेस, रफ़ीक़ी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियां एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस शामिल थे। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की हवाई और युद्ध संबंधी क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुँचा। आईएएफ की हवाई हमलों की तीव्रता से यह ज़ाहिर हो गया है कि इन हवाई अड्डों, विमानों और वहाँ तैनात हथियार प्रणालियों को पहुँचाया गया नुकसान, 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर आईएएफ द्वारा पीएएफ के हवाई अड्डों को पहुँचाए गए कुल नुकसान से कहीं ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली की परिपक्वता को भी साबित कर दिया, जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन-केंद्रित रणनीति का मुक़ाबला करने में सक्षम है। हालाँकि, आईएएफ को भविष्य में, अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के ख़िलाफ़ किसी भी सीमित संघर्ष की स्थिति में अपने प्लेटफ़ॉर्म, हथियारों और प्रणालियों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, तेज़ गति से लगातार सीखते रहने की आवश्यकता होगी। भविष्य के युद्ध-क्षेत्रों में, लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों का सामना करने के लिए, ज़्यादा एकीकरण और तालमेल की ज़रूरत होगी। वर्तमान में चल रहे सुधारों और संरचनात्मक पहलों पर शायद फिर से विचार करना पड़े, ताकि एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जा सके जो भारत-विशिष्ट हो और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीखे गए अनुभवों पर आधारित हो। हालांकि, दुनिया भर में चल रहे संघर्षों से कई रणनीतिक और परिचालन संबंधी सबक मिलते हैं, लेकिन भारत को दूसरी जगहों से युद्ध-लड़ाई के मॉडल उठाने और उन्हें अपने रणनीतिक और परिचालन वातावरण पर लागू करने के प्रति सावधान रहना चाहिए।

टिप्पणी

आम मरीजों के हक की रक्षा

ये नहीं कहा जा सकता कि आवश्यक दवाओं के मामले में कंपनियों से कोई नाइसांफी होती है। फिर भी दवा कंपनियों ने 2013 से ही मूल्य नियंत्रण आदेश के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। अब उन्हें एक न्यायिक सफलता मिली है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय के परिणामस्वरूप बहुत-सी जरूरी दवाएं मूल्य नियंत्रण की श्रेणी से बाहर हो जाएंगी। कोर्ट ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश- 2013 की भाषा में मौजूद खामियों का लाभ दवा कंपनियों को दिया है। उसने कहा कि मूल्य संबंधी विनियमों को उन दवाओं पर लागू नहीं किया जा सकता, जिनका स्पष्ट रूप से उपरोक्त आदेश में उल्लेख नहीं है। सरकार इसी आदेश के तहत आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) बनाती है, जिनकी मनमाने ढंग से कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। विशेषज्ञों के मुताबिक इस व्यवस्था को नाकाम करने के लिए कंपनियां मूल दवा में मामूली हेरफेर कर उसके नए संस्करण बनाती रही हैं।

ये दवाएं अलग नाम से बाजार में उतारी जाती हैं। अब तक 2013 के आदेश की भावना के अनुरूप सरकार ऐसी दवाओं को एनएलईएम में शामिल करती आई है। फिलहाल, इस सूची में 348 दवाएं हैं, जिनके सभी संस्करण (खूराक मात्रा और पॉवर के रूप में) उस सूची में शामिल हैं। अब ये सूरत बदल सकती है। हालांकि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है, लेकिन आशंका है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं दिया, तो बीच की अवधि में बहुत-सी दवाएं आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हो जाएंगी।

इसलिए जरूरी है कि सरकार भाषा की खामियों को दुरुस्त करते हुए 2013 के आदेश को नए सिरे जारी करे। यहां उल्लेखनीय है कि कंपनियों को एनएलईएम के तहत आने वाली दवाओं की कीमत साल में एक बार बढ़ाने का अधिकार 2013 के आदेश के तहत मिला हुआ है। गुजरे वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वे इनके दाम बढ़ाती रही हैं। अंतर सिर्फ यह है कि ऐसी वृद्धि का तर्क उन्हें पेश करना पड़ता है, जिस पर सरकार की नज़र रहती है। अतः ये नहीं कहा जा सकता कि इन दवाओं के मामले में कंपनियों से कोई नाइसांफी होती है। लेकिन दवा कंपनियों ने 2013 से ही उपरोक्त आदेश के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। अब उन्हें एक न्यायिक सफलता मिली है। मगर सरकार को यह याद रखना चाहिए कि आम मरीजों के हक की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है।

ब्लॉग

(12 मई) पर विशेष

उम्मीद और भरोसे की मिसाल नर्सों को मिले पूर्ण सम्मान का दर्जा

'हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं' थीम पर मनेगा यह खास दिवस

मुकेश कुमार शर्मा

पूर्ण समर्पण और निःस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा में हर पल तत्पर रहने वाली नर्सों को आज स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ के रूप में देखा जाता है। आपात स्थितियों में चिकित्सकों के कंधे से कन्धा मिलाकर घंटों मरीजों की देखभाल में तत्पर नर्सों के जज्बे में कभी कोई कमी नजर नहीं आती। उनके इसी समर्पण को सैल्यूट करने के लिए हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन यह प्रेरणा देता है कि उम्मीद और भरोसे की मिसाल बन चुकी नर्सिंग सेवा को पूर्ण सम्मान का दर्जा मिले, सुरक्षित कार्य वातावरण मिले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता मिले ताकि उनके कार्यबल को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के साथ और उन्नत बनाया जा सके। इस साल इस खास दिवस की थीम- 'हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं' तय की गयी है, जो यह साबित करती है कि एक बीमार को पूर्ण स्वस्थ बनाने में नर्स की कितनी बड़ी भूमिका है। आज के दिन उन नर्सों के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनके अथक प्रयास से व्यक्ति को नया जीवन तक नसीब होता है। चाहे छोटे या बड़े बच्चे हों, पुरुष हों या महिलाएं, युवक हों या युवती, हर किसी के स्वास्थ्य देखभाल में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है।

अस्पताल पहुँचने पर सबसे पहले आगे बढ़कर स्वागत के साथ मरीज का मनोबल बढ़ाने और उम्मीद बंधाने वाली नर्स ही होती हैं, जो कि समय से दवा और भोजन का ख्याल रखती हैं। जीवन रक्षक उपकरणों के प्रबन्धन के साथ ही मरीज के लिए शांत वातावरण की व्यवस्था का भी वह ध्यान रखती हैं। मरीज के पूरी तरह स्वस्थ होने की सबसे ज्यादा ख़ुशी देखभाल करने वाली उन्हीं नर्स के चेहरे पर देखी जा सकती है और वह ख़ुशी-ख़ुशी मरीज को घर के लिए विदा भी करती हैं। आपात स्थितियों या दुर्घटनाओं में घायलों को संभालना जहाँ बड़ी मुश्किल का काम होता है, वहीं वह उसे एक चुनौती के रूप में देखती हैं और सेवा में तत्पर हो जाती हैं। उस समय वह न काम के घंटे को देखती हैं और न ही भूख या प्यास। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उन्हें हर जरूरी सुविधाएं अस्पताल में मुहैया करायी जाएँ, जिसकी सही मायने में वह पूरी तरह हकदार हैं। अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला हो या आपरेशन थियेटर में परेशान मरीज वह उन्हें धीरज दिलाने और साहस बढ़ाने का काम भी ख़ुशी-ख़ुशी करती हैं। सुरक्षित प्रसव के बाद नवजात को देखकर जितनी ख़ुशी मां को होती है, उससे कहीं ज्यादा ख़ुशी की झलक नर्स के चेहरे पर साफ़ देखी जा सकती है।

मरीजों की सेवा के अलावा वह अस्पतालों के कुशल संचालन में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। एक तरह से कहा जाए तो वह मरीजों, चिकित्सकों और परिवार वालों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती हैं । मरीजों के सारे रिकार्ड और दस्तावेज को संभालकर रखने की जिम्मेदारी निभाती हैं। साफ़-सफाई के साथ संक्रमण नियन्त्रण के हर जरूरी बिन्दुओं का भी वह ख्याल रखती हैं। किसी विषम परिस्थिति के समय वह भावनात्मक मदद के साथ सांत्वना प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। मरीजों के सही स्वास्थ्य की जानकारी का इंतजार कर रहे परिजनों को भी ढांढस बंधाने का कार्य करती हैं।

अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटेंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल को 'लेडी विद द लैम्प' भी कहा जाता है, क्योंकि क्रीमिया युद्ध के दौरान जख्मी सैनिकों की सेवा की मिसाल पेश करने के साथ ही साफ़-सफाई का पूरा ख्याल रखकर उन्होंने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी थी। आज के दिन नर्सों को सम्मानित करना और उनके लिए समारोह का आयोजन करना उनके जज्बे को ताकत देने का काम करेगा। उनको अवार्ड या प्रतीक चिन्ह भेंटकर भी उनकी हौसला अफजाई की जा सकती है। यह दिन हर किसी को याद दिलाता है कि नर्सें स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं, जो मरीजों को उम्मीद और भरोसा देती हैं। ऐसे में उनके सशक्तिकरण पर गंभीरता से कार्य करने के साथ ही उनके उच्च कोटि के प्रशिक्षण पर भी जोर देने की जरूरत है, ताकि वह आपात स्थितियों को सँभालने में दक्ष होने के साथ ही जीवन रक्षक उपकरणों का उचित प्रबन्धन भी आसानी से कर सकें। इसके साथ ही नर्सिंग सेवा को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इसमें निवेश की भी जरूरत है ताकि वह भविष्य की चुनौतियों का आसानी से सामना करने के योग्य बन सकें। ऐसा करना अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी जरूरी है ताकि वह बीमार को शीघ्र स्वस्थ बनाकर फिर जीवन की मुख्यधारा से जोड़कर फिर से कार्य दायित्व को संभालने के योग्य बना सकें।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल

मां-बाप या मैं... इस जिद ने तोड़ा घर, जज की एक बात से दो साल बाद एक हुए पति पत्नी

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों में बढ़ती दूरियों और परिवार में बदलते सामाजिक माहौल की तस्वीर को उजागर कर दिया है। करीब 2 साल से अलग रह रहे पति-पत्नी आखिरकार परिवार न्यायालय की पहल और जज की समझाइश के बाद फिर से एक हो गए। मामला सास-ससुर के साथ रहने को लेकर शुरू हुआ था, जिसने धीरे-धीरे इतना बड़ा रूप ले लिया कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में हुई समझाइश ने टूटे रिश्ते को नया जीवन दे दिया।

जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक की शादी वर्ष 2022 में बुलंदशहर निवासी ज्योति से हुई थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने सामान्य रहे, लेकिन बाद में परिवार के भीतर तनाव बढ़ने लगा। विवाद की मुख्य वजह युवक के बुजुर्ग माता-पिता थे। महिला अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी, जबकि युवक अपने माता-पिता से बेहद जुड़ा हुआ था और वह उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।

सास-ससुर को लेकर हुई तकरार

धीरे-धीरे यही बात पति-पत्नी के बीच झगड़े की वजह बन गई। आए दिन घर में कहासुनी होने लगी। पति जहां अपने माता-पिता और पत्नी दोनों को साथ लेकर चलना चाहता था, वहीं पत्नी चाहती थी कि पति केवल उसके और बच्चे के साथ रहे। विवाद बढ़ता गया और परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

बेटे की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए बुजुर्ग माता-पिता ने भी समझदारी दिखाई। उन्होंने घर में पार्टिशन करवा दिया, ताकि बहू और बेटे को अलग स्पेस मिल सके और विवाद खत्म हो जाए। इसके बाद महिला अपने पति और बेटे के साथ घर के अलग हिस्से में रहने लगी, लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में आई कड़वाहट कम नहीं हुई।

एक सप्ताह कहकर मायके गई, फिर नहीं लौटी

कुछ समय बाद महिला अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। उसने पति से कहा था कि वह एक सप्ताह बाद लौट आएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। इसके बाद पति कई बार उसे मनाने और वापस लाने के लिए मायके गया, लेकिन महिला ने साफ शर्त रख दी कि अगर साथ रहना है तो उसे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ना पड़ेगा। पति इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि वह अपने माता-पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। बाद में महिला ने पति और सास-ससुर पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर दिया। मामला पारिवारिक न्यायालय तक पहुंच गया और करीब दो साल तक दोनों अलग रहे।

लोक अदालत में बदली रिश्तों की तस्वीर

दो साल के अलगाव के दौरान दोनों के रिश्ते लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गए थे। परिवार के लोग भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका था और परिवार पूरी तरह टूटने की ओर बढ़ रहा था। इस बीच राष्ट्रीय लोक अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश चंद्र प्रकाश तिवारी ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने पति-पत्नी को रिश्ते की अहमियत बताई और उनके छोटे बेटे के भविष्य का हवाला दिया।

काफी देर तक चली बातचीत और समझाइश के बाद दोनों पक्ष नरम पड़े। जज ने उन्हें समझाया कि अहंकार और जिद किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकती है, लेकिन समझदारी और बातचीत रिश्तों को बचा सकती है। आखिरकार पति-पत्नी समझौते के लिए तैयार हो गए और महिला 2 साल बाद फिर से अपने पति के साथ ससुराल लौट गई।

लोक अदालत में समझौते के बाद अदालत परिसर में मौजूद लोगों ने इस फैसले की सराहना की। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि अदालतों में सिर्फ कानूनी फैसले ही नहीं, बल्कि कई बार टूटते परिवारों को जोड़ने का काम भी किया जाता है।

महाराणा प्रताप का जीवन राष्ट्रभक्ति व स्वाभिमान का प्रतीक : डॉ एमपी सिंह

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486 वीं जयंती रविवार को सनातन अखाड़ा के कलेक्ट्रेट सामने स्थित कैंप कार्यालय पर श्रद्धा और गौरव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के त्याग, शौर्य और मातृभूमि रक्षा के संकल्प को याद करते हुए उन्हें राष्ट्र गौरव का प्रतीक बताया।मुख्य वक्ता डॉ एमपी सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और संघर्ष की अमर गाथा है। उन्होंने कहा महाराणा ने घास की रोटी खा ली, लेकिन मातृभूमि का सम्मान कभु झुकने नहीं दिया कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वरिष्ठ जनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। सनातन अखाड़ा अध्यक्ष रमेश उपाध्याय ने उपस्थित लोगों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, गिरीश नारायण सिंह, डॉ सीताशरण त्रिपाठी, जगजीत सिंह छंगू, एमपी त्रिपाठी, प्रवीन कुमार अग्रवाल, अजय सिंह लीडर, राकेश पालीवाल, नरेन्द्र सिंह, विजय सिंह रघुवंशी, संजय सोमवंशी, इन्द्रजीत सिंह रुपेश सिंह, दिनेश चौरसिया, विनोद कुमार पांडे, पंकज दूबे, रजनीश मिश्रा, गोविन्द तिवारी टाडा, धनंजय सिंह, विक्रम सिंह, अनिल सिंह,समर बहादुर सिंह, अजय सिंह फौजी, मनीष जायसवाल, जंग बहादुर सिंह देवेन्द्र सिंह, श्याम बहादुर सिंह, विनोद मिश्रा, आत्मजीत सिंह टीटू, बद्री पाण्डेय समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

बॉयफ्रेंड से की शादी, पैर टूटा तो छोड़ा साथ, चली गई मायके... प्रेग्नेंसी रिपोर्ट आई तो करने लगी ये जिद

आर्यावर्त संवाददाता

मिर्जापुर। खबर यूपी के मिर्जापुर से है। यहां एक गांव के एक युवक ने अपनी गर्भवती प्रेमिका से मंदिर में दोबारा शादी की है। युवक का पैर टूट जाने के बाद प्रेमिका मायके चली गई थी। गर्भवती हुई तो वो प्रेमी संग रहने की जिद करने लगी। यही नहीं उसने पुलिस से भी इसकी शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पंचायत कराई। युवक के परिजन राजी हो गए, प्रेमिका दोबारा शादी करने के लिए अड़ गई तो पास के मंदिर में शादी कराई गई।

मामला सोनभद्र जनपद के एक गांव का है। यहां रहने वाली एक युवती मिर्जापुर जनपद के राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से प्रेम करती थी। प्रेम इतना बढ़ा कि दोनों ने घर वालों को बिना बताए शादी कर ली। युवती को युवक अपने घर लाया ,कुछ दिन दोनों एक साथ रहे। इस बीच युवक का एक सड़क हादसे में पैर टूट गया। युवती ने तब युवक को अकेला छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। नाराज युवक युवती को मायके लेने नहीं गया। जब युवती को पता चला कि प्रेग्नेंट है तो अपने परिवार जनों के साथ थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। लड़के की परिजन लड़की को घर ले जाने के लिए राजी हो गए मगर लड़की दोबारा शादी करने के लिए जिद करने लगी तो परिजनों ने पास के मंदिर में शादी दोबारा कराई। युवक अपने गर्भवती प्रेमिका से दोबारा शादी कर घर ले गया।

मामले में क्या बोले थाना प्रभारी?

राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि एक युवती ने शिकायत की थी। दोनों पक्षों को बुलवाकर समझा दिया गया है। एक साथ रहने को राजी हो गए हैं।युवती को लड़के वाले अपने साथ ले गए। इधर अब ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

मामूली विवाद में सेना के जवान को बना दिया अपराधी, भेजा जेल

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार/सुल्तानपुर। शनिवार को रास्ते के विवाद का निरीक्षण करने गए लेखपाल की चाभी निकालकर निस्तारण की मांग करना सेना के जवान को महंगा पड़ गया। पुलिस ने लेखपाल की मनगढ़ंत तहरीर के आधार पर बिना जांच पड़ताल के सेना के जवान को गम्भीर धाराओं में जेल भेज दिया। मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के चका परसीपुर गांव से जुड़ा है।जहां शनिवार को शिकायती पत्र की जांच करने पहुंचे लेखपाल बॉर्डर का मामला बताते हुए नाप जोख करने से मना कर दिए। लेखपाल का कहना था कि मामला कुड़वार व दूबेपुर विकास खंड के बॉर्डर है। जब तक परसीपुर व बभनगवां दोनों गांव के लेखपाल राजस्व अभिलेखों के साथ उपस्थित नही होंगे। तब तक निस्तारण नहीं हो सकता। इसी बात पर नाराज होकर गांव निवासी फौजी जवान खुर्शीद अली पुत्र शमशेर जो बीएसएफ में मेघालय में तैनात है। वह नाराज हो गया और लेखपाल के बाइक की चाभी निकालते हुए कहा कि पहले हमको लिखित दीजिए कि अभी निस्तारण नहीं हो पाएगा तब यहां से जाइए। इतने पर लेखपाल शिव प्रसाद ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचे राजस्व निरीक्षक शिव प्रसाद मौके पर पहुंचे।और लेखपाल सहित फौजी जवान को लेकर थाने आ गए। उसके बाद लेखपाल द्वारा नॉर्मल तहरीर दी गई थी लेकिन गंम्भीर धारा बनाने के लिए तहरीर बदल दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रविवार को सेना के जवान को जेल भेज दिया।

स्टेशन से रेल चलने के पांच मिनट बाद हत्या, फिर फेंकी लाश, 7KM तक गए कातिल

चलती ट्रेन में यात्री की गोली मारकर हत्या की गई। मामले की जांच पुरानी दुश्मनी, आपसी विवाद और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। आस-पास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों से संपर्क किया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
-प्रशांत वर्मा, एसपी रेलवे, प्रयागराज

आर्यावर्त संवाददाता

चंदौली। चंदौली के पीडीडीयू नगर में ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन को कुचमन से सकलडीहा तक 8 किमी की दूरी तय करने में 35 मिनट का समय लगता है। रविवार को ट्रेन में सवार यात्रियों के लिए 35 मिनट का सफर खौफ के बीच बीता। कुचमन स्टेशन से ट्रेन के चलते ही बदमाशों ने मंगरू की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 7 किमी तक इसी ट्रेन से यात्रा की और सकलडीहा रेलवे स्टेशन से पहले उतर कर भाग गए।

ताड़ीघाट पैसेंजर रविवार की सुबह 6:24 बजे पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म 3 से खुली। इस समय तक सब कुछ सामान्य था। ट्रेन सुबह 6:36 बजे कुचमन पहुंची और 06:40 बजे यहां से चली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन चलते ही कोच में मंगरू का दो युवकों से विवाद शुरू हो गया। एक युवक ने मंगरू की कनपटी से सटा कर पिस्टल से गोली मार दी। इस बीच ट्रेन एक किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी और दरियापुर के समीप पहुंची थी। यहां हमलावरों ने शव को नीचे फेंक दिया। इसके बाद लगभग 7 किमी की दूरी इसी ट्रेन से तय की। इस दौरान यात्री डर सहमे रहे। ट्रेन सकलडीहा रेलवे स्टेशन के समीप 7:11 बजे पहुंची और गति धीमी हुई तो बदमाश उतर कर भाग निकले। इसके बाद यात्रियों ने सकलडीहा रेलवे स्टेशन पर वारदात की सूचना दी।

चलती ट्रेन में यात्री की गोली मारकर हत्या

पं. दीनदयाल उपाध्याय से दिलदारनगर होते हुए ताड़ीघाट जा रही पैसेंजर ट्रेन में रविवार की सुबह बदमाशों ने एक यात्री की कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। घटना कुचमन और सकलडीहा रेलवे स्टेशन के बीच हुई। हत्या के बाद बदमाशों ने मृतक का शव ट्रेन से नीचे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। सकलडीहा रेलवे स्टेशन के पूर्व ट्रेन की धीमी गति का फायदा उठाकर आरोपी ट्रेन से उतरकर भाग गए। जीआरपी ने मृतक की पहचान मंगरू (34) पुत्र दूधनाथ, निवासी चौधरी मोहल्ला, जिला गाजीपुर के रूप में की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन पीडीडीयू जंक्शन से रविवार सुबह 7.30 बजे प्लेटफार्म नंबर तीन से रवाना हुई। कुचमन स्टेशन से आगे बढ़ते ही एक कोच में दो यात्रियों के बीच विवाद हो गया। बहसबाजी के दौरान एक पक्ष के दो युवकों में से एक ने जेब से पिस्टल निकालकर मंगरू की कनपटी पर सटाकर गोली मार दी। यात्री खून से लथपथ होकर सीट के पास गिर गया। बदमाशों ने शव को कुछ देर बाद चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और पिट्ठू बैग लेकर सकलडीहा रेलवे स्टेशन के पूर्व ही ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। यात्रियों द्वारा सूचना मिलने पर चंदौली और सकलडीहा पुलिस, जीआरपी और दिलदारनगर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक किनारे मृतक का शव बरामद किया गया। सकलडीहा के क्षेत्राधिकारी कृष्णमुरारी शर्मा ने बताया कि यात्रियों से पूछताछ में सामने आया है कि हत्यारोपी पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से ट्रेन में सवार हुए थे। उन्होंने मंगरू नामक यात्री की कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच सकलडीहा पुलिस, पीडीडीयू नगर पुलिस, जीआरपी और तीन थानों की संयुक्त टीम कर रही है।

सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों की तलाश जारी

एसपी जीआरपी प्रशांत वर्मा, सीओ जीआरपी वाराणसी कुंवर प्रभात सिंह, सीओ सकलडीहा कृष्णमुरारी शर्मा और सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी रेलवे ने कुचमन से जमानिया स्टेशन तक सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान की कोशिश की।

दस साल पहले चलती पैसेंजर ट्रेन में गोली मारकर जीआरपी कर्मी की हुई थी हत्या

चंदौली में जिस तरह ताडीघाट पैसेंजर ट्रेन में हमलावरों ने दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या की है। ठीक 10 वर्ष पहले भी बक्सर पैसेंजर ट्रेन में बदमाशों ने चलती ट्रेन में जीआरपी के दो आरक्षियों को गोली मार दी थी। इसमें एक आरक्षी की मौत हो गई थी। 14 मई 2016 की रात में बक्सर से पीडीडीयू जंक्शन आ रही बक्सर पैसेंजर ट्रेन में इक्का-दुक्का यात्री थे। चौसा में आठ बदमाश ट्रेन में चढ़े।

ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी और पौनी कमरपुर हॉल्ट स्टेशन के पास बदमाशों ने जीआरपी के आरक्षी अभिषेक (31) और नंदलाल (35) पर फायरिंग कर दी। नंदलाल की बांह में और अभिषेक के सीने में गोली लगी। दोनों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। गोली लगने से अभिषेक की मौत हो गई। नंदलाल जख्मी हो गए। घटना के बाद बदमाश आरक्षियों के असलहे लेकर भाग गए थे। घटना के बाद डीजीपी के आदेश पर कांस्टेबलों को पिस्टल दी गई और ट्रेनिंग दी गई।

कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध खनन का आरोप, ग्रामीणों ने एसडीएम से लगाई गुहार

कादीपुर/सुल्तानपुर। तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़गांव में कब्रिस्तान की सुरक्षित भूमि पर अवैध खनन और कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गांव के ही ऋषि तिवारी पुत्र लालमणि तिवारी समेत अन्य लोगों पर दबंगई के बल पर सरकारी जमीन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों के अनुसार गाटा संख्या 386 (रकबा 0.190 हेक्टेयर) और 385 क (रकबा 0.0530 हेक्टेयर), जो राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, पर 4 और 5 मई की रात जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन किया गया। आरोप है कि रात के अंधेरे में करीब 100 ट्रॉली मिट्टी वहां से हटाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपित पक्ष के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया और मारपीट पर आमादा हो गए।

हाईवे किनारे मिले 27 गोवंश, 24 की मौत से मचा हड़कंप

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को टांडा-बांदा हाईवे किनारे बड़ी संख्या में मृत और घायल गोवंश मिलने से सनसनी फैल गई। सेमरी चौकी क्षेत्र के माधवपुर देवरी गांव के पास करीब 300 मीटर के दायरे में गोवंश बिखरे पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। प्रशासन की ओर से की गई गणना में कुल 27 गोवंश पाए गए, जिनमें 20 गाय और चार बैल मृत मिले, जबकि तीन गायें गंभीर रूप से घायल अवस्था में थीं। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल गोवंशों का उपचार शुरू कराया। घटना की जानकारी मिलते ही उपजिलाधिकारी प्रभात कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी प्रमोद मिश्रा समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

मृत गोवंशों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिससे मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह ने बताया कि ग्राम माधवपुर के प्रधान द्वारा सूचना दी गई थी कि गांव के बाहर अकबरपुर-सुल्तानपुर स्टेट हाईवे के किनारे सुनसान स्थान पर मृत और घायल गोवंश पड़े हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि गोवंशों को किसी वाहन से यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना ट्रांजिट के दौरान हुई या फिर कहीं और गोवंशों की हालत बिगड़ने पर उन्हें यहां लाकर डंप किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। सर्विलांस की मदद से वाहन और आरोपियों की तलाश के लिए एसओजी समेत चार टीमों का गठन किया गया है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मृत गोवंशों का सम्मानजनक निस्तारण कराया जा रहा है और मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धूमधाम से मनाया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

सुलतानपुर। भारतीय संस्कृति, आस्था और श्रद्धा के प्रतीक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार से हुई, जहां महिलाओं ने विधिवत पूजन-अर्चन कर शिव मंदिर और सीता कुंड घाट तक भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में भाजपा नगर अध्यक्ष रीना जायसवाल, नगर उपाध्यक्ष मंजू तिवारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। इसके बाद सभागार में ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य शैलेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.), डीसी एनआरएलएम के.डी. गोस्वामी, भाजपा पदाधिकारी, महिला मोर्चा प्रतिनिधि, अपना दल के जिलाध्यक्ष राकेश वर्मा समेत अनेक गणमान्य लोग और आमजन शामिल हुए।

नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज... भंगेल एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक का टेंशन खत्म, इतना रास्ता हुआ चौड़ा, पीक आवर्स में लगता था जाम

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे डीएससी रोड और भंगेल एलिवेटेड रोड के आसपास अभी यातायात कुछ हद तक आसान हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने यहां सड़क चौड़ीकरण और फुटपाथ हटाने का काम शुरू किया है, जिसके बाद सेक्टर- 41 आगाहपुर से लेकर NSEZ तक का सफर काफी तेज हो गया। जो दूरी पहले 30 से 40 मिनट तक में तय होती थी अब वही सफर 8 से 10 मिनट में पूरा हो रहा है।

हालांकि, राहत के बावजूद कई जगहों पर अभी भी जाम की बड़ी समस्या बनी हुई है, जिस पर काम अभी किया जाना बाकी है। जानकारी के मुताबिक, नोएडा के दादरी सूरजपुर छलेरा डीएससी रोड पर बना भंगेल एलिवेटेड रोड शहर की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर- 41 आगाहपुर से शुरू होकर फेज- 2 के गंदे नाले तक जाता है।

करीब 5 I5 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 600 करोड रुपए की लागत आई है। इस रोड को शुरू करने का मकसद डीएससी रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना था। लेकिन रोड शुरू होने के बाद भी कुछ तकनीकी खामियों और गलत ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से वाहन चालक रोजाना जाम में फंस रहे थे।

प्राधिकरण ने क्या किया बदलाव?

स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के अनुसार जाम के पीछे दो बड़ी वजह सामने आई थी। पहली वजह थी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने से पहले सड़क के एक तरफ बना फुटपाथ और दूसरी तरफ डिवाइडर इससे सड़क संकरी हो रही थी और वाहनों की गति धीमी पड़ रही थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी एलिवेटेड रोड पर चढ़ने से पहले बना यू टर्न। सेक्टर- 42, सेक्टर- 45 सदरपुर और आसपास के इलाकों से आने वाले वाहन इसी यूटर्न का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे एलिवेटेड रोड पर चढ़ने वाले वाहनों की लंबी कतारे लग जाती थी।

सुबह और शाम के पीक आवर में यह हालत इतनी खराब हो जाते थे कि लोग कई किलोमीटर लंबे जाम में फंस जाते थे। लगातार शिकायतों के बाद नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को यहां सुधार कार्य शुरू किया। अगाहपुर की तरफ से बने फुटपाथ को कुछ हिस्सों में तोड़ दिया गया है, जिससे सड़क की चौड़ाई बढ़ गई है। अब एलिवेटेड रोड के नीचे से सीधे सेक्टर- 49 चौराहे की तरफ जाने वाले वाहन आसानी से निकल पा रहे हैं। इससे ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है और एलिवेटेड रोड पर चढ़ने वाले लोगों को भी राहत मिली है। प्राधिकरण का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी और जाम में कमी आएगी।

किन इलाकों को मिला सीधा फायदा?

हालांकि, सड़क चौड़ीकरण के बाद कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एलिवेटेड रोड से नीचे उतरते ही फेज- 2 के गंदे नाले के पास अभी भी भारी जाम लग रहा है। यहां कई वाहन चालक गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड में आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह अवस्थित हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस और प्राधिकरण अभी तक इस हिस्से के लिए कोई स्थानीय समाधान तैयार नहीं कर पाए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यहां ट्रैफिक सिग्नल बारगेटिंग और सख्त निगरानी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में फिर वही हालत बन सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर भंगेल एलिवेटेड रोड बनने से नोएडा के कई सेक्टर और इलाकों को सीधा फायदा मिला है। इन सेक्टर में 41,49 50,51 82,101 106, 110 बरौला सलारपुर और भंगेल जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि पहले ऑफिस टाइम में घर से निकलना किसी बड़ी चुनौती से काम नहीं था। डीएससी रोड पर घंटों जाम लग रहा था, लेकिन अब यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है।

महिला आरक्षण पर सपा के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। संसद में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल का विरोध किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कुड़वार ब्लॉक सभागार परिसर में आयोजित महिला जन आक्रोश अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा एवं महिला कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सपा पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी वास्तविक सोच जनता के सामने उजागर कर दी है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी आगामी चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का विरोध सपा और विपक्षी दलों को वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगा। भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों का विरोध कर रहा है। भाजपा आईटी सेल की जिला सह-संयोजक कुसुमलता मौर्य एवं माधुरी मिश्रा के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में धम्मौर, कुड़वार, शिवनगर, पीपरगांव और बल्दीराय मंडल की बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक कुसुमलता मौर्य और माधुरी मिश्रा ने उपस्थित महिलाओं का आभार व्यक्त किया। जिला मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी ने जानकारी दी कि 12 मई को सदर विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं बरौसा में समाजवादी पार्टी और सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी।

बच्चा अगर विकलांग दोस्त की करें बात तो माता पिता को करने चाहिए ये चार काम

अगर आपका बच्चा अक्सर एक ऐसे बच्चे के बारे में बताता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है तो आप अपने बच्चे को यह जरूर सिखाएं कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है?

आपका बच्चा ठीक है। पूरी तरह स्वस्थ है। मगर उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक साथी शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। आपका बच्चा आपको उसके बारे में बताता है, लेकिन उससे बात नहीं करता। ऐसे में आपको अपने बच्चे को शारीरिक विकलांगता के बारे में सही ज्ञान देना होगा, ताकि वह उस बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार न करे, क्योंकि सही जानकारी और समझ के अभाव में बच्चे अक्सर अक्षमता को लेकर गलत धारणाएं बना लेते हैं, जो भेदभाव को बढ़ावा दे सकती हैं।

कैसे समझाएं

बच्चे से आपको खुले मन से बातचीत करनी होगी। आप बच्चे से उसके दोस्त के बारे में पूछें कि उसे उस बच्चे में क्या पसंद है और क्या नहीं। आप धैर्य से बच्चे की बात सुनें। ऐसा करके ही आप उसके मन की बात को समझ पाएंगी और उसे सही ज्ञान दे पाएंगी। आपका सही मार्गदर्शन बच्चे को दोस्त बनाने और उस बच्चे के साथ एक मजबूत बंधन बनाने में मदद कर सकता है।

एक उदाहरण

जब आप बच्चे को समझाने का प्रयास कर रही हों तो उससे सरल भाषा में बात करें और उदाहरणों का उपयोग करें। विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं की तुलना करके उसे समझाएं कि हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ सफल व्यक्तियों के उदाहरण दें, जिन्होंने अक्षमता को चुनौती दी और जीवन में आगे बढ़े।

मदद के लिए प्रेरित करें

अपने बच्चे को शारीरिक रूप से असक्षम बच्चे के साथ खेलने और गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। उसे उस बच्चे की मदद करने के तरीके बताएं, जैसे कि सामान उठाना या वॉशरूम लेकर जाना। आप बच्चे के सभी सवालों का जवाब ईमानदारी और स्पष्टता से दें, लेकिन गलत जानकारी कभी न दें।

आपकी भाषा

आप खुद 'विकलांग' जैसे शब्दों के बजाय 'विशेष आवश्यकता वाले' या 'अलग क्षमता वाले' जैसे शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि आप जो भी शब्द ऐसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगी, वह उनको ही सीखेगा और उनका उपयोग करेगा। खराब भाषा का उपयोग शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे के मन को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए आप बच्चे को ऐसी किताबें और कहानियां पढ़कर सुनाएं, जिनमें विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले लोग हों।

मन को बनाएं निर्मल

बच्चे में सहानुभूति और सहिष्णुता विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। माता-पिता के रूप में आपकी भूमिका है कि आप अपने बच्चे को एक ऐसे समाज के लिए तैयार करें, जहां सभी को समान रूप से स्वीकार किया जाता है। स्कूल काउंसलर आपके बच्चे को समझने और उसे मार्गदर्शन देने में मदद कर सकते हैं। वहीं कई ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध हैं, जो आपको इस विषय पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

दुखी हो तो सहारा बने

बाल मनोवैज्ञानिक गार्गी मालगुडी कहती हैं, माता-पिता को अपने बच्चे को समझाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए। यदि आपके बच्चे का दोस्त शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे समझाना चाहिए कि उस बच्चे का दोस्त बनकर रहे और उसकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहे। माता-पिता को अपने बच्चे को थोड़ा संवेदनशील बनाने पर फोकस करना चाहिए।

आप अपने बच्चे से कहें कि क्लास में अक्षम दोस्त के साथ बैठे, उसकी पढ़ाई में मदद करे। आप उसे सिखाएं कि वह किसी भी बच्चे की शारीरिक बनावट का मजाक न उड़ाए और अगर कोई अन्य ऐसा करे तो उसे भी रोके। छुट्टी के समय बस तक पहुंचाकर उसको सीट पर बैठने में मदद करे। कभी वह दुखी हो तो उसे भावनात्मक सहारा दे। टीजिंग या गलत शब्दावली का उपयोग कभी न करे, न ही किसी अन्य को बोलने दे।

दिल को रखना चाहते हैं सेहतमंद? आहार में ये एक बदलाव आपके लिए बहुत लाभकारी

हृदय रोगों का खतरा वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। कम उम्र के लोग यहां तक कि बच्चे भी हृदय रोग और इसके जोखिम कारकों का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी इसका प्रमुख कारण हो सकती है। विशेषतौर पर खान-पान पर ध्यान न देना, नमक-प्रोसेस्ड चीजों का अधिक सेवन हृदय रोगों के लिए प्रमुख कारक हो सकते हैं।

अध्ययनों से पता चलता है कि खान-पान में बदलाव, विशेषतौर पर खाने के लिए सही तेल के चयन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ऑलिव ऑयल (जैतून के तेल) को इसके लिए बहुत फायदेमंद पाया गया है। ऑलिव ऑयल को आहार का हिस्सा बनाकर न सिर्फ आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं साथ ही इससे हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों को भी कम किया जा सकता है।

क्यों फायदेमंद माना जाता है ये ऑयल

ऑलिव ऑयल (जैतून के तेल) में पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो बल्ड प्रेशर को दुरुस्त रखते हैं। यह तेल हृदय को भी स्वस्थ बनाए रखता है। जैतून के तेल में विटामिन ई, के आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं। इस तेल का इस्तेमाल करने से कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं।

इस तेल मौजूद पॉलीफेनोल्स धमनियों को रिलैक्स करने और खोलने में मदद करते हैं। इससे हृदय की सेहत दुरुस्त रहती है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। यह तेल गुड कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाने और बैड कॉलेस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है। जैतून के तेल में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं।

वजन कम करने में भी सहायक

वजन कम करने के लिए आप जैतून के तेल को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इस तेल से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे खाने की क्रेविंग्स कम होती हैं और पेट भरे रहने का एहसास होता है। इससे धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है और मेटाबॉलिक रेट भी बेहतर होता है। जैतून के तेल में सूजनरोधी गुण होने से यह सूजन कम करता है और गठिया जैसे रोगों में राहत देता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अनिल बंसल बताते हैं, प्रतिदिन एक चम्मच जैतून का तेल सलाद में डालकर खाने या खाना पकाने में इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इस तेल का अधिक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस तेल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुण और सैचुरेट फैट होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और आप संक्रमण तथा बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।

अल्जाइमर रोग का भी कम होता है जोखिम

हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने ऑलिव ऑयल के सेवन को बहुत लाभकारी पाया है। एक शोध में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि प्रतिदिन लगभग एक चम्मच जैतून के तेल का सेवन डिमेंशिया के कारण मृत्यु के जोखिम को लगभग 30 प्रतिशत तक कम कर सकती है। 28 वर्षों तक अमेरिका में 92,000 से अधिक वयस्कों के डेटा का अवलोकन करने पर पता चला कि ऑलिव ऑयल न सिर्फ अल्जाइमर से बचाने में लाभकारी है साथ ही इससे इन रोगों के कारण मौत के खतरे को भी कम कर सकते हैं।

कई बीमारियों का कारण बन सकती है नींद न आने की समस्या, आप भी हैं परेशान तो करें ये तीन काम

शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक माना जाता है। ये मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की सेहत को ठीक रखने के लिए जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं, जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है।

नींद न आने की समस्या के कई कारण हो सकते हैं। मानसिक तनाव या चिंताएं अक्सर दिमाग को इतना सक्रिय कर देती हैं कि व्यक्ति आराम से सो नहीं पाता। इसके अलावा चाय, कॉफी, सिगरेट और अन्य कैफीनयुक्त पदार्थों का सेवन करने वालों को भी नींद विकारों की दिक्कत हो सकती है।

अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ प्रकार की क्रोनिक बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां और मानसिक रोग के शिकार लोगों की भी नींद अक्सर बाधित रहती है।

नींद न आने की समस्या

नींद न आने की समस्या (अनिद्रा) एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सोने में कठिनाई होती है या रात में अक्सर उसकी नींद टूट जाती है। नींद की कमी का असर दीर्घकालिक रूप से कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं (जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक विकार और अन्य क्रोनिक बीमारियां) को बढ़ाने वाली हो सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, नींद की बढ़ती समस्याओं के लिए मोबाइल या कंप्यूटर जैसे स्क्रीन्स का अधिक इस्तेमाल भी माना जा सकता है। इन उपकरणों से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के लिए आवश्यक मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है।

स्मार्टफोन और स्क्रीन से दूरी बनाएं

सोने से 1-2 घंटे पहले स्मार्टफोन, कंप्यूटर, या टेलीविजन का इस्तेमाल न करें। इन उपकरणों की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को प्रभावित करती है, जिससे नींद आने में परेशानी होती है। मेलाटोनिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो नींद को नियंत्रित करता है। अनिद्रा के शिकार लोग डॉक्टर से सलाह लेकर इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर नींद की समस्या किसी मानसिक विकार जैसे अवसाद या एंग्जायटी के कारण है, तो इसके लिए मनोचिकित्सक से सलाह लें।

सोने का समय निर्धारित करें

हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक नियमित होता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके अलावा कमरे को नींद के अनुकूल बनाएं। कमरा शांत, अंधेरा वाला और ठंडा होना चाहिए। अनुकूल माहौल में अच्छी नींद मिलती है।

शारीरिक व्यायाम करें

नियमित शारीरिक व्यायाम-योग नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक है। व्यायाम करने से शरीर को थकावट महसूस होती है, जिससे सोने में आसानी होती है। ध्यान रहे कि सोने से पहले व्यायाम न करें, क्योंकि यह शारीरिक उत्तेजना बढ़ा सकता है। ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीक और मांसपेशियों को आराम देने वाली एक्सरसाइज सोने से पहले करने से तनाव कम होता है और नींद में सुधार होता है।

छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, PhonePe का एआई करेगा आसान पेमेंट सेटअप

फोनपे ने एक नया एआई टूल लॉन्च किया है, जो बिजनेस के लिए पेमेंट सिस्टम जोड़ने की प्रक्रिया को काफी आसान और तेज बना देगा। कंपनी का कहना है कि जो काम पहले कई हफ्तों में होता था, अब वह कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा।

मिनटों में शुरू होगा पेमेंट सिस्टम

फोनपे ने अपने मर्चेंट्स के लिए एआई -पावर्ड इंटीग्रेशन सिस्टम पेश किया है। इसकी मदद से बिजनेस बिना ज्यादा तकनीकी जानकारी के भी फोनपे का पेमेंट गेटवे आसानी से जोड़ सकेंगे। कंपनी के मुताबिक, पहले पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन में कोडिंग, डॉक्यूमेंट पढ़ने और बार-बार तकनीकी बदलाव करने में कई हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अब एआई एजेंट के जरिए यह काम बातचीत जैसी आसान प्रक्रिया में मिनटों में हो जाएगा।

एआई खुद समझेगा पेमेंट सिस्टम

फोनपे के CTO और फाउंडर Rahul Chari ने कहा कि यह एआई सिर्फ कोड लिखने वाला टूल नहीं है, बल्कि यह पेमेंट सिस्टम को भी समझता है। कंपनी ने इसमें अपनी खास Integration Intelligence तकनीक जोड़ी है, जिससे इंटीग्रेशन ज्यादा स्मार्ट और आसान बन गया है।

छोटे कारोबारियों को होगा बड़ा फायदा

कंपनी का कहना है कि इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मझोले कारोबारियों यानी SME सेक्टर को मिलेगा। अक्सर इन बिजनेस के पास बड़े डेवलपर या टेक्निकल टीम नहीं होती, जिससे पेमेंट सिस्टम जोड़ने में परेशानी आती है। अब एआई टूल की मदद से वे बिना तकनीकी झंझट के जल्दी ऑनबोर्ड हो सकेंगे और तेजी से ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करना शुरू कर पाएंगे।

डेवलपर्स का समय भी बचेगा

फोनपे के मुताबिक, यह सिस्टम सही API और पेमेंट सेटअप अपने आप फॉलो करेगा। साथ ही एरर हैंडलिंग और जरूरी तकनीकी सुधार भी एआई खुद करेगा। इससे डेवलपर्स का काफी समय बचेगा और कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विस सुधारने पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी।

एआई फीचर्स पर आगे भी रहेगा फोकस

कंपनी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में एआई से जुड़े और भी नए फीचर्स लाए जाएंगे। PhonePe का मानना है कि एआई टेक्नोलॉजी भविष्य में डिजिटल पेमेंट और बिजनेस ऑपरेशन को और ज्यादा आसान बना सकती है।

क्या है 'पंप एंड डंप' स्कैम, जिससे मिनटों में डूब जाती है निवेशकों की मेहनत की कमाई?

पंप एंड डंप' स्कैम में ज्यादातर पेनी स्टॉक्स का इस्तेमाल होता है. पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे ₹1, ₹2 या ₹5. इन शेयरों को ऑपरेट करना आसान होता है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है और थोड़ी सी खरीदारी से भी इनकी कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है.

कुछ दिन पहले शेयर बाजार में निवेशकों की मेहनत की कमाई को लूटने वाले ठगों पर सेबी (SEBI) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अहमदाबाद, मुंबई और गुरुग्राम में एक साथ छापेमारी कर सेबी ने ₹300 करोड़ के 'पंप एंड डंप' स्कैम का पर्दाफाश किया है। इस घोटाले में 15 से 20 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें कुछ लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स ने बनाया था। ये ठग यूट्यूब, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए निवेशकों को झांसा देते थे। आइए, समझते हैं कि आखिर ये 'पंप एंड डंप' स्कैम है क्या, कैसे काम करता है

क्या है 'पंप एंड डंप' स्कैम

'पंप एंड डंप' एक ऐसा घोटाला है, जिसमें ठग शेयर बाजार में छोटे-मोटे या पेनी स्टॉक्स की कीमतों को पहले आसमान पर चढ़ाते हैं और फिर अचानक उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेते हैं। इस दौरान आम निवेशक, जिन्हें रिटेल इनवेस्टर्स कहते हैं, फंस जाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई डूब जाती है। ये स्कैम सोशल मीडिया के जमाने में और खतरनाक हो गया है, क्योंकि ठग अब यूट्यूब, व्हाट्सऐप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स के जरिए लाखों लोगों तक अपनी झूठी बातें पहुंचा देते हैं।

इस स्कैम का तरीका बड़ा आसान लेकिन बेहद चालाकी भरा है। पहले ठग किसी कंपनी के शेयर को बहुत कम दाम पर खरीद लेते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पर उस शेयर की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये शेयर जल्द ही चांद पर पहुंचेगा, इसमें निवेश करने से मोटा मुनाफा होगा। कई बार तो वो फर्जी खबरें भी फैलाते हैं, जैसे कि उस कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कोई बड़ी कंपनी उसे खरीदने वाली है। इन सबके लिए वो बड़े यूट्यूबर्स, इनफ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया स्टार्स का सहारा लेते हैं, जो अपने फॉलोवर्स को उस शेयर में पैसा लगाने की सलाह देते हैं।

जैसे ही लोग इन बातों में आकर उस शेयर को खरीदने लगते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत आसमान छूने लगती है। निवेशकों को लगता है कि जो उन्हें बताया गया, वो सच है और वो और पैसे उस शेयर में झोंक देते हैं। लेकिन असल में ये सब एक जाल होता है। जैसे ही शेयर की कीमत ठगों के मनमाफिक ऊंचाई पर पहुंचती है, वो अपने सारे शेयर बेच देते हैं, यानी 'डंप' कर देते हैं। इससे शेयर की कीमत अचानक धड़ाम से गिर जाती है, और आम निवेशक के हाथ में सिर्फ नुकसान रह जाता है।

कैसे काम करता है ये स्कैम?

'पंप एंड डंप' स्कैम का तरीका समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, एक कंपनी का शेयर ₹1 पर ट्रेड कर रहा है। ठग इस शेयर को बड़े पैमाने पर खरीद लेते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पर इसके बारे में हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कंपनी जल्द ही ₹50 तक जाएगी, क्योंकि इसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला है या कोई बड़ी कंपनी इसे खरीदने वाली है। लोग इन बातों पर भरोसा करके शेयर खरीदने लगते हैं। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती है, शेयर की कीमत ₹10, ₹20, फिर ₹40 तक पहुंच जाती है।

निवेशकों को लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं, और वो और शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही शेयर की कीमत ठगों के टारगेट तक पहुंचती है, वो अपने सारे शेयर बेच देते हैं। इससे मार्केट में शेयरों की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, और कीमत ₹2-3 तक गिर जाती है। जो निवेशक ऊंचे दाम पर शेयर खरीद चुके थे, उनके हाथ में सिर्फ घाटा रह जाता है। इस पूरे खेल में ठग मिनटों में करोड़ों कमा लेते हैं, और निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं।

इस स्कैम में कई बार निवेशक अपने शेयर बेच भी नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही ठग शेयर को 'डंप' करते हैं, शेयर का दाम तेजी से गिरने लगता है और वह अपने लोअर सर्किट पर पहुंच जाता है। लोअर सर्किट लगते ही शेयर में बिकवाली रुक जाती है, क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिलता। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर महीनों तक हर दिन लोअर सर्किट पर अटका रहता है। निवेशकों को पता चल जाता है कि वे फंस चुके हैं, लेकिन उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता।

पेनी स्टॉक्स है ठगों का पसंदीदा हथियार

'पंप एंड डंप' स्कैम में ज्यादातर पेनी स्टॉक्स का इस्तेमाल होता है। पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे ₹1, ₹2 या ₹5। इन शेयरों को ऑपरेट करना आसान होता है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है और थोड़ी सी खरीदारी से भी इनकी कीमत में बड़ा उछाल आ सकता है। इसके अलावा, इन कंपनियों की जानकारी मार्केट में कम होती है, जिससे ठगों को फर्जी खबरें फैलाने का मौका मिल जाता है।

सेबी की सख्ती, ठगों की अब खैर नहीं

सेबी इस तरह के घोटालों पर लगाम कसने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। हाल के सालों में सेबी ने कई बड़े नामों पर कार्रवाई की है, जो 'पंप एंड डंप' स्कैम में शामिल थे। मिसाल के तौर पर, बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर करने के लिए सेबी ने एक साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया था। इस स्कैम में यूट्यूब वीडियोज के जरिए शेयर की कीमत को गलत तरीके से बढ़ाया गया था, और ठगों ने ₹58.01 करोड़ का मुनाफा कमाया था।

इसी तरह, मशहूर मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन और उनके 11 साथियों पर भी सेबी ने कार्रवाई की थी। सेबी ने उन पर ₹11.37 करोड़ की गैरकानूनी कमाई का आरोप लगाया और उन्हें शेयर बाजार से बैन कर दिया। भसीन पर आरोप था कि वो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स देकर पहले खुद उन शेयरों को खरीद लेते थे और फिर कीमत बढ़ने पर बेच देते थे।

हाल ही में सेबी ने 20 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स वाले यूट्यूबर रविंद्र बालू भारती पर भी शिकंजा कसा है। रविंद्र पर आरोप है कि वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए निवेशकों को गलत स्टॉक टिप्स देकर 'पंप एंड डंप' स्कैम को बढ़ावा दे रहे थे। सेबी की इन कार्रवाइयों से साफ है कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

निवेशकों के लिए सेबी की सलाह

सेबी ने निवेशकों को इस तरह के घोटालों से बचने के लिए कई सलाह दी हैं। सेबी का कहना है कि निवेशक किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स की अच्छे से जांच कर लें। अगर कोई शेयर अचानक बिना किसी वजह के तेजी से चढ़ रहा है, तो उसमें निवेश करने से पहले सावधान रहें। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर मिलने वाली स्टॉक टिप्स पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि वो केवल रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें।

आबादी के आधार पर हुआ परिसीमन तो दक्षिण भारत के अधिकारों पर होगा असर: थरूर

सैन फ्रांसिस्को। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने चेतावनी दी कि अगर संसद की सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया तो दक्षिण भारत के राज्यों को ऐसा लग सकता कि उनके अधिकार कम हो गए हैं। वहीं, भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत को स्वाभाविक रूप से ज्यादा सांसद मिलने चाहिए। उन्होंने यह बात अमेरिका के स्टेनफर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित 'स्टेनफर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस' के दौरान कही। चर्चा का विषय 'इंडिया यानी भारतः विकास, प्रशासन और पहचान' था।

शशि थरूर ने कहा कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बढ़ते अंतर के कारण भविष्य में कुछ लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग कर सकते हैं, जिसका तमिल लोग विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए वहां के एक सांसद पर ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का बंटवारा केवल आबादी के हिसाब से हुआ, तो उत्तर भारत के राज्यों के पास संसद में इतना बहुमत हो सकता है कि वे अपनी राय दक्षिण भारत पर थोप सकें।

थरूर ने यह भी कहा कि बहुत बड़े राज्यों के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 28 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का इतना बड़ा होना सही नहीं लगता। उन्होंने याद दिलाया कि जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने राज्य को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। इस पर जवाब देते हुए अन्नामलाई ने कहा, आम लोग अपने सांसद को केवल अखबारों में या फीता काटने वाले कार्यक्रमों में ही देखते हैं। देश को इस मुद्दे का समाधान चाहिए। उन्होंने कहा, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो, तो तमिलनाडु को 50 सीटें मिलतीं। लेकिन नए मॉडल में उसे 59 सीटें मिल रही हैं, यानी नौ सीटें ज्यादा।

अन्नामलाई ने कहा, जनगणना के आधार पर उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सांसद मिलना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा, अगर हर राज्य केवल यह सोचता रहेगा कि उसे फायदा हो रहा है या नुकसान, तो इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ऐसा समाधान चाहती है, जिसमें किसी राज्य को नुकसान न हो। बहस के दौरान शशि थरूर ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसे परिसीमन विधेयक से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, मौजूदा संसद में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण ही दिया जा सकता है।

17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक पर हुए मतदान में 298 सांसदों ने समर्थन किया जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। इसके बाद सरकार ने कहा कि वह परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था, जिसमें महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना था। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। लेकिन परिसीमन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण मौजूदा लोकसभा सीटों में ही दिया जाए।

रिश्तों में नया मोड़ : नौ साल बाद चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, व्यापार और ताइवान पर होगी बड़ी बातचीत

बीजिंग। करीब नौ साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। ऐसे समय में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जब अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जारी युद्ध, होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ी हुई है। साथ ही ताइवान, व्यापार और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी लगातार बना हुआ है।

व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी अन्ना केली के मुताबिक, ट्रंप बुधवार शाम बीजिंग पहुंचेंगे। गुरुवार को उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। कार्यक्रम में टेंपल ऑफ हेवन का दौरा और राजकीय भोज भी शामिल है। शुक्रवार को दोनों नेता एक बार फिर मुलाकात करेंगे, जहां चाय पर चर्चा और वर्किंग लंच का आयोजन होगा। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि इस साल के अंत में शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा भी हो सकती है। ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ और व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें तेज हैं। दोनों देशों ने रविवार को घोषणा की कि चीन के उपप्रधानमंत्री हे लिफेंग 12 और 13 मई को दक्षिण कोरिया में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ अंतिम दौर की व्यापार वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि इन बातचीतों का मकसद ट्रंप की यात्रा से पहले व्यापारिक तनाव को कम करना है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह वार्ता दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति और हालिया फोन बातचीत के आधार पर आगे बढ़ेगी। बातचीत में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर फोकस रहेगा। इस बीच, ताइवान का मुद्दा भी ट्रंप-शी वार्ता के केंद्र में रहने वाला है। ट्रंप की यात्रा से पहले वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ताइवान को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन अमेरिका की आधिकारिक नीति पहले जैसी ही बनी हुई है। अमेरिकी अधिकारियों ने ताइवान को हथियार बिक्री का मुद्दा भी उठाया। उनका दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती वर्ष में ही ताइवान को पिछले प्रशासन के पूरे चार वर्षों की तुलना में कहीं अधिक हथियार बिक्री को मंजूरी दी थी।

ट्रंप के सख्त रुख के बीच क्यूबा के पास अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ीं

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और क्यूबा के बीच बढ़ते तनाव के बीच क्यूबा के तट के पास अमेरिकी सैन्य खुफिया गतिविधियों में हाल के महीनों में अचानक तेजी देखी गई है। सोमवार को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सेना की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाली उड़ानों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट में फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के सार्वजनिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 4 फरवरी से अब तक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना कम से कम 25 निगरानी उड़ानें संचालित कर चुकी हैं। इनमें ज्यादातर उड़ानें क्यूबा की राजधानी हवाना और सैंटियागो डी क्यूबा के आसपास देखी गईं। कुछ विमान क्यूबा के तट से महज 40 मील यानी करीब 64 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए।

इन मिशनों में मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना के पी-8ए पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान का इस्तेमाल किया गया। यह विमान निगरानी, टोही और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ उड़ानों में ऐसे विशेष विमान और ड्रोन भी शामिल थे, जो सिग्नल इंटेलिजेंस और हाई-एल्टीट्यूड रिकॉनिसेंस मिशनों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा आठ महीने बाद जेल से रिहा, भ्रष्टाचार के मामले में ठहराए गए थे दोषी

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड की राजनीति में दशकों तक विवाद और ध्रुवीकरण का केंद्र रहे पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को आज बैंकॉक की जेल से रिहा कर दिया गया। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एक साल की सजा काट रहे 76 वर्षीय थाकसिन ने आठ महीने जेल में बिताए, जिसके बाद उन्हें पैरोल पर रिहाई मिली।

बैंकॉक की क्लोंग प्रेम सेंट्रल जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए करीब 300 समर्थक और राजनीतिक सहयोगी जुटे। थाकसिन सफेद पोलो टी-शर्ट और नीली पैंट में जेल से बाहर निकले, जहां उनके परिवार ने उन्हें गले लगाया। समर्थकों ने वी लव थाकसिन के नारे लगाए और उन्हें लाल गुलाब भेंट किए। हालांकि, उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। थाकसिन शिनावात्रा दूरसंचार कारोबार से जुड़े अरबपति कारोबारी रहे हैं। उन्होंने 1998 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और 2001 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। 2006 में सेना ने तख्तापलट कर उनकी सरकार को हटा दिया था। उस समय वह विदेश दौरे पर थे। इसके बाद थाई राजनीति लगभग दो दशकों तक गहरे राजनीतिक संघर्ष और ध्रुवीकरण का शिकार रही। थाकसिन पर सत्ता के दुरुपयोग, अपने कारोबारी हितों को फायदा पहुंचाने और सरकारी लॉटरी परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उन्हें अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था। हालांकि, 2023 में वह स्वदेश लौटे और अदालत के सामने पेश हुए। शुरुआत में उन्हें आठ साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में थाईलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने इसे घटाकर एक साल कर दिया।

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए थाकसिन को बैंकॉक के पुलिस अस्पताल के विशेष कक्ष में सजा काटने की अनुमति मिली थी। इस फैसले पर विरोधियों ने उन्हें विशेष सुविधा दिए जाने का आरोप लगाया। इसके बाद सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल में सजा पूरी करने का आदेश दिया था।

स्वास्थ्य कारणों से मिली पैरोल की मंजूरी

हाल ही में न्याय मंत्रालय की एक समिति ने अच्छे आचरण, बढ़ती उम्र और दोबारा अपराध की कम संभावना को देखते हुए उन्हें पैरोल देने की मंजूरी दी। रिहाई के बाद अगले चार महीनों तक वह निगरानी में रहेंगे। उन्हें बैंकॉक स्थित अपने घर में रहना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ब्रेसलेट पहनना होगा और नियमित रूप से अधिकारियों को रिपोर्ट करनी होगी।

थाकसिन की बेटी बनी थी सबसे युवा पीएम

थाकसिन की बेटी पैतोंगटार्न शिनावात्रा 2024 में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थीं, लेकिन 2025 में एक विवादित फोन कॉल सामने आने के बाद संवैधानिक अदालत ने उन्हें पद से हटा दिया था। इस साल हुए आम चुनाव में थाकसिन समर्थित फेउ थाई पार्टी तीसरे स्थान पर रही।

निशिकांत दुबे का हमला: 370 का विरोध करने पर गिरफ्तार हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू ने ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। डॉ मुखर्जी उस समय जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और वहां प्रवेश के लिए जरूरी परमिट सिस्टम का विरोध कर रहे थे।

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि 11 मई 1953 का दिन कांग्रेस के इतिहास का एक काला अध्याय है। उनके अनुसार, डॉ. मुखर्जी ने नेहरू को अपने आंदोलन के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। इस जानकारी के आधार पर नेहरू ने शेख अब्दुल्ला और कैलाश नाथ काटजू को निर्देश दिया कि वे 11 मई को डॉ. मुखर्जी को गिरफ्तार कर लें। बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अनुच्छेद 370 के विरोध में आज ही के दिन (11 मई 1953) को जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था।

सांसद ने आगे दावा किया कि कश्मीर की जेल में बंद रहने के दौरान डॉ. मुखर्जी की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने बाद में इस पूरे मामले को दबा दिया था। दुबे के मुताबिक, नेहरू ने 12 दिनों के विदेश दौरे पर जाने से पहले कैलाश नाथ काटजू को लिखित निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि देशव्यापी आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया जाए और इसमें शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

लगाए गंभीर आरोप

निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि नेहरू ने उस दौर के दो प्रमुख अखबारों 'प्रताप' और 'मिलाप' के प्रकाशन को पूरी तरह रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि नेहरू परिवार के हाथ खून और धोखे से रंगे हुए हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को भी दुबे ने नेहरू-गांधी परिवार पर निशाना साधा था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि यह परिवार भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था।

सोमनाथ मंदिर का भी किया जिक्र

भाजपा नेता ने नेहरू पर सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इस संबंध में धमकी भरे पत्र लिखे थे। दुबे ने 22 अप्रैल 1951 के एक सरकारी नोट का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने मंदिर के उद्घाटन को रोकने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि नेहरू ने सोमनाथ मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से माफी मांगी थी और संसद में भी ऐसा ही बयान दिया था।

पीएम मोदी की अपील पर सियासी घमासान, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने की सत्र बुलाने की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक संकट पर की गई 7 अपीलों पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी। चिदंबरम ने कहा कि सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई 'सात अपीलों' के बारे में देश को जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यालय से बहुत गंभीर निर्देश आए हैं इनका कारण क्या है?

उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाना चाहिए, देश को भरोसे में लेना चाहिए और हमें मौजूदा हालात की असलियत के बारे में बताना चाहिए, जिनकी वजह से ये अपील करना जरूरी हो गया है। उन्होंने MyGov की एक पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया एक्स पर दिया।

MyGov की पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात अपीलें बताई गई थीं । इन अपीलों को मुश्किल वैश्विक समय में भारत को

मज़बूत बनाने के लिए बताया गया। MyGov की इस पोस्ट का शीर्षक है राष्ट्र सबसे पहले, कर्तव्य आराम से ऊपर! इसमें PM मोदी की नागरिकों से की गई अपील का जिक्र था कि जहां भी मुमकिन हो, 'वर्क फ्रॉम होम' को प्राथमिकता दें, ईंधन की खपत कम करें, एक साल तक विदेश यात्रा से बचें, स्वदेशी उत्पाद अपनाएं, खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें और बेवजह सोने की खरीदारी कम करें। पोस्ट में आगे कहा गया कि जिम्मेदारी की ये सामूहिक भावना भारत को और भी ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकती है।

कार्ति चिंतबंरम का बयान ऐसे समय में आया है जब तेहरान ने अमेरिका समर्थित 'नौ-सूत्रीय शांति योजना' का मुकाबला करने के लिए एक '14-सूत्रीय योजना' तैयार की है। मीडिया रिपोर्स्ट के मुताबिक, ईरानी प्रस्ताव में तीन चरणों वाले एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है। इसमें 30 दिनों का एक ऐसा चरण शामिल है, जिसे अस्थायी संघर्ष-विराम को दोनों देशों की दुश्मनी को स्थायी रूप से बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। बातचीत के हिस्से के तौर पर तेहरान ने प्रतिबंधों में राहत, ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियों को हटाने, इस क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और लेबनान में इजराइली सैन्य अभियानों को रोकने की मांग की है।

करिश्मा तन्ना ने प्रेग्नेंसी में दिखाया ग्लैमरस अवतार, मोनोकिनी पहन दिए पोज

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने हाल ही में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं। फोटोज में वो काफी ग्लैमरस लुक में नजर आईं।

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं। वो अक्सर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं। उनका ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। लुक की बात करें, तो करिश्मा ब्लैत एंड व्हाइट मोनोकिनी पहने नजर आईं। गॉग्लस लगाए वो काफी ब्यूटीफुल दिख रही है। करिश्मा ने कई पोज भी दिए। तस्वीरों में उनका बेबी बंप भी नजर आ रहा है। फैंस तस्वीरों पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। करिश्मा ने इससे पहले ब्लैक मोनोकिनी में भी कई फोटोज शेयर की थी। सेल्फी लेते हुए वो अपनी बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रहीं थी। बता दें, एक्ट्रेस इस साल अगस्त में अपने पहले बेबी का वेलकम करने वाली हैं। उन्होंने अपने पति के साथ फोटोज शेयर कर फैंस के साथ ये गुड न्यूज शेयर की। करिश्मा तन्ना ने साल 2022 में वरुण बंगेरा के साथ शादी की थी। अब ये कपल शादी के चार साल बाद पेरेंट्स बनने वाले हैं।

राम चरण की पेड्डी ने विदेश में रचा इतिहास, प्रीमियर से पहले ही महज 4 घंटे में बना दिया ये तगड़ा रिकॉर्ड

पेड्डी साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है। इस अपकमिंग फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर ने लीड रोल प्ले किया है। पेड्डी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट पहले ही पीक पर है। वहीं इस फिल्म ने 4 जून 2026 को अपनी वर्ल्डवाइड रिलीज से पहले नॉर्थ अमेरिका में अपनी प्री-सेल्स के साथ ही इतिहास रच दिया है। बता दें कि पेड्डी के मेकर्स ने हाल ही में कंफर्म किया था कि इस फिल्म का फाइनल एडिट लॉक हो चुका है। ये फिल्म 3 जून 2026 को अपने वर्ल्डवाइड प्रीमियर के लिए तैयार है, जिसके बाद 4 जून को इसे दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा। अपने ग्रैंड प्रीमियर से पहले ही, पेड्डी ने रिकॉर्ड तोड़ प्री-सेल्स के साथ एक कमाल कर दिया है। दरअसल नॉर्थ अमेरिका में पेड्डी के डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे प्रत्यंगिरा सिनेमाज की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला है। इसी के साथ फिल्म ने महज चार घंटों के भीतर $100य का आंकड़ा पार कर लिया, जो इतने कम समय में किसी भी भारतीय फिल्म की टिकट सेल के लिए एक नया बेंचमार्क है।

इस उपलब्धि की सबसे खास बात ये है कि फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। यह जबरदस्त रिस्पॉन्स राम चरण के लिए फैंस की दीवानगी और बुची बाबू सना के ग्रैंड विजन के प्रति लोगों के बढ़ते एक्साइटमेंट को दिखाया है। बता दें कि पेड्डी नॉर्थ अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में एक बड़े लेवल पर रिलीज होने के लिए तैयार है। पेड्डी को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेकर्स फिल्म से राम चरण के दमदार ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्ट्राइकिंग पोस्टर्स और इंटेंस झलकियां लगातार शेयर कर रहे हैं। इस बढ़ते हाइप में फिल्म का म्यूजिक भी चार चांद लगा रहा है, जो पहले ही चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। ए।आर। रहमान द्वारा कंपोज किया गया पहला सिंगल, चिकीरी चिकीरी, अपनी जबरदस्त एनर्जी की वजह से तुरंत लोगों की जुबान पर चढ़ गया और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके दूसरे गाने रई रई रा रा ने भी अपनी शानदार कोरियोग्राफी और विजुअल्स से एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। इसे यूट्यूब पर 66 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं, जिनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नज़र आएंगे। वेंकट सतीश किलारू के बैनर वृद्धि सिनेमाज और माइथ्री मूवी मेकर्स के सहयोग से ये फिल्म बनी है। धुरंधर और राजा शिवाजी की बड़ी सफलता के बाद, जियो स्टूडियोज इसे नॉर्थ इंडिया में रिलीज करेगा। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 3 जून 2026 को होगा, जिसके बाद 4 जून 2026 को यह दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 के 50 दिन पूरे, रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर बनी दूसरी सबसे कमाऊ भारतीय फिल्म

रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधरः द रिवेंज ने इतिहास की किताबों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है, क्योंकि उनकी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 50 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और एक ऐतिहासिक थिएटर रन के साथ बॉक्स ऑफ़सि पर अपना दबदबा बनाए हुए है। रिलीज के 50 दिन पूरे होने के साथ ही, इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने अपने नाम एक और नई उपलब्धि जोड़ ली है।

धुरंधरः द रिवेंज ने 7 मई को बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे किए हैं। इन 50 दिनों में रणवीर की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। किसी भी बॉलीवुड फिल्म को धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कई जबरदस्त छक्के और चौके लगाने होंगे।

हालांकि हफ्तों बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार गति बनाए रखने में कामयाब रही है। धुरंधर 2 ने अपनी थिएट्रिकल यात्रा की शुरुआत पहले हफ्ते में 674।17 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त कमाई के साथ की। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 263।65 करोड़ रुपये और कमाए, और उसके बाद तीसरे हफ्ते में 110।60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

आने वाले हफ्तों में भी यही सिलसिला जारी रहा, और चौथे हफ्ते में फिल्म ने 54।70 करोड़ रुपये की कमाई की। पांचवें, छठे और सातवें हफ्ते में क्रमशः 19।52 करोड़ रुपये, 12।45 करोड़ रुपये और 5।58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई के साथ, फिल्म ने अपनी कुल कमाई को एक बहुत बड़े आंकड़े तक पहुंचा दिया।

हाल ही में बने एक नए रिकॉर्ड के साथ, इस फिल्म ने बाहुबली 2: द कंक्लूजन (1788।60 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया भर में किसी भी भारतीय फिल्म की कुल कमाई के मामले में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। यह फिल्म अब दंगल (1968।03 करोड़ रुपये) के ठीक पीछे है। सैकनिल्क के मुताबिक, धुरंधर 2 ने दुनिया भर में 1791।55 करोड़ रुपये का बिजनेस कर चुकी है,

यह सचमुच इस फिल्म के लिए एक असाधारण उपलब्धि है कि इसने भारत में इस साल की 1000 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। वहीं, 2026 की यह सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप फिल्म बन गई है।

इस फ्रैंचाइजी ने खुद भी इतिहास रच दिया है। धुरंधर सीरीज़ के कुल कलेक्शन ने अब दुनिया भर में 3,100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, और इसके साथ ही यह दुनिया भर में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रैंचाइजी बन गई है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा।

RNI No: UPHIN/2014/57034

Website : aryavartkranti.com

*सम्पादकः प्रभात पांडेय

सम्पर्क: 9839909595, 8765295384

Email: aryavartkrantidainik@gmail.com